पर्मोदकोहली से पहले, जे।
2010 (2)

बनाम
भारत संघ और अन्य उत्तरदाता
1997 का CWP नंबर 7283
07 जनवरी, 2010

हेल्ड, कि परिशिष्ट-II के साथ विनियमन173 r3ead के नंगे पढ़ने से
सेना पेंशन नियमों में से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की चोट सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है, रिलीज के समय उनकी विकलांगता 70 पर प्रमाणित की जा रही है, वह विकलांगता पेंशन के हकदार हैं। थकाऊ आदेश संचार, 11 दिसंबर को हटा दिया गया। 1996, पेंशन। 1 इस आधार पर याचिकाकर्ता कि चोटको और न ही सैन्य सेवा द्वारा उत्तेजित किया गया है। मैं उनके संचार में नहीं हूँ «मेरी जमानतदार भारत सरकार द्वारा इस तरह की एक राय XX10 को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और मेडिकलरिलीज बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के लिए नहीं।
(पैरा १६)
आगे आयोजित, कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के स्पष्ट और श्रेणीबद्ध निष्कर्षों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास पहाड़ी क्षेत्रों पर ड्राइव करने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। वह एक आधिकारिक कर्तव्य के लिए विस्तृत था। ब्रेक विफलता के कारण दुर्घटना हुई। अदालत के अंतिम फैसले में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निरंतर चोट सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है

(पैरा २१)
इसके अलावा, कि उत्तरदाताओं का स्टैंड कि याचिकाकर्ता को उनके कार्यकाल की समाप्ति के कारण छुट्टी दे दी गई थी और इस प्रकार, विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं हैं, यह भी होना है

सेना के नियमों के अधिकार नियमों और विनियमन53 के नियम 4 के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया गया, सेना के नियमों के विनियमन53 स्पष्ट रूप से प्रदान करता

है कि जहां एक अधिकारी कार्यकाल के पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो जाता है और वह किसी भी विकलांगता से पीड़ित है या सैन्य द्वारा उत्तेजित या उत्तेजित है। सेवा और सेवा चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई सेवा को भी राष्ट्रपति के विवेक पर पेंशन का विकलांगता तत्व प्रदान किया जा सकता है।

(पैरा 26)

इसके अलावा, कि याचिकाकर्ता को उनके कार्यकाल के पूरा होने पर छुट्टी नहीं दी गई थी। रिकॉर्ड पर रखी गई पूरी सामग्री इस तथ्य के लिए सूचक है कि याचिकाकर्ताओं की रिलीज़ उनके कार्यकाल की समाप्ति के कारण नहीं थी, लेकिन विकलांगता के कारण उन्हें कम चिकित्सा श्रेणी में रखकर उन्हें क्षेत्र क्षेत्र में सैन्य सेवा के लिए अनफिट पाते हुए। यह इन परिस्थितियों में है कि याचिकाकर्ता ने गतिहीन/प्रकाश शुल्क पर सेवा में विस्तार का दावा किया है, जो उनकी प्रार्थनाओं में से एक है। विनियमन53 के संदर्भ में, एक व्यक्ति जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होता है या कार्यकाल के पूर्ण होने पर जारी होता है, लेकिन सैन्य सेवा द्वारा बढ़े या बढ़े हुए विकलांगता से पीड़ित है, भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर पेंशन के विकलांगता तत्व का भी हकदार है। इस प्रकार, इस तरह के एक भड़कीले मैदान पर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना कानून में और वास्तव में पूरी तरह से अनुचित है। अधिकार नियमों के नियम 4, स्पष्ट रूप से प्रदान करता है

परमदित्सिंगीV भारत संघऔर अन्य

विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए सेवा से अमान्य होना एक आवश्यक शर्त है। याचिकाकर्ता को कम चिकित्सा श्रेणी में रखकर विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया है। यूआईएस विकलांगता को रिलीज़मेडिकल बोर्ड द्वारा 70% पर मूल्यांकन किया गया है, विकलांगता पेंशन के लिए उनके दावे को विवादित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 26)

परमदीप सिंह, याचिकाकर्ता में याचिकाकर्ता।

सुश्री गीता सिंहवाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर I के लिए।

पर्मोदकोहली, जे।

1.) सेवा और विकलांगता पेंशन के अनुदान में विस्तार से इनकार करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस याचिका में इस याचिका को चुनौती दी है कि इस याचिका में पी -2 और पी -3 दोनों के आदेशों को चुनौती दी गई है।

2.) इस याचिकाकर्ता को दाखिल करने के लिए अग्रणी तथ्यों को संक्षेप में नोटिस

किया जाता है। याचिकाकर्ता11 मार्च, 1989 को 2लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में आयुक्त थे। उन्हें 503एएससी बटालियन, लेह पर तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता को एक प्रशासनिक कर्तव्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

3.) 2 दिसंबर, 1989 को, याचिकाकर्ता अपनी बटालियन से दूसरे तक आगे बढ़ रहा था

आधिकारिक वाहन में बटालियन 528। वह खुद वाहन चला रहा था। जब वाहन लेह-कारगिल रोड पर पठार साहिब गुरुद्वारा के पास पहुंचा, तो यह पहाड़ी इलाके पर पलट गया। याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उक्त दुर्घटना यांत्रिक विफलता के कारण थी। याचिकाकर्ता और वाहन में यात्रा करने वाले अन्य अधिकारी घायल हो गए। याचिकाकर्ता को सेना के लिए निकाला गया था

अस्पताल और उसके बाद कमांड अस्पताल, पश्चिमी कमांड, चंडिमंदिरकैंट।

4.) दुर्घटना के कारणों में पूछताछ करने के लिए एक अदालत की जांच की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:-

2 दिसंबर, 1989 को (वह 503एएससीबीएन के जोंगा नंबर 84बी2 7680L वाहन 5. पर था।)।

2. वाहन लगभग 1300 बजे पाथर साहब के पास एक दुर्घटना के साथ मिले। (गवाह नंबर 1, 3 और 4)

3. डोंगा नंबर 84बी2 76801, ब्रेक विफलता के कारण एक दुर्घटना के साथ मिला। (गवाह नंबर 1. 3, 4. 8 और ईएमई दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म)

4. 2/l1 परम गहरी सिंह 3 ors के साथ वाहन चला रहा था (गवाह नंबर 1, 2, 3, 4)

(ए) नं। 13846234 हवलदार माउंटआरएस यादव

(b) नं। 13848867 इ्क्षजगत बहादुर

(C) नंबर 13894 790एसपीअशु सिंह

5. लेफ्टिनेंटपरमदीप सिंह ने वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक की विफलता के कारण ऐसा नहीं कर सका। उसने पहाड़ी की ओर से इसे लाकर वाहनों को रोकने की कोशिश की। वाहन ने बड़े बोल्डर को मारा और सड़क के दाईं ओर पठार साहब से लगभग 300 गज की दूरी पर मुड़ गया (गवाह नंबर 1. 2, 3, 4 और 5)

6. परमदीप सिंहने सही रिट पर बड़ी चोट लगी और 3 अन्यने मामूली चोटों को बनाए रखा। 3ओआरएस के लिए कोई बड़ी चोट नहीं थी। ऑफर घटना के माध्यम से सचेत था (गवाह नंबर 1, 2, 3, 4 और 7)।

7. परमदीप सिंहका संचालन 2 दिसंबर, 1989 को सही कलाई और कण्डरा और प्रकोष्ठ की मांसपेशियों की मरम्मत के यौगिक फ्रैक्चर के लिए 153 GH पर किया गया था (गवाह नंबर 6)।

8. अधिकारी ने 27 नवंबर, 1989 को 503एएससीबीएन द्वारा आयोजित हिल ड्राइविंगटेस्ट पास किया था। उनके पास एक एमआईएलड्राइविंग लाइसेंस और एक सिविल ड्राइविंग लाइसेंस था। (अर्क संलग्न)

9 सीओ 503एएससीबीएन ने 2/एलटीपरमदीप सिंह को वाहनों को चलाने की अनुमति दी थी। (गवाह नंबर 7 और CO द्वारा हस्ताक्षरित CERT का CTC)

10. फाउल प्ले का कोई सबूत नहीं था।

(५) पूर्वोक्त निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने पर अदालत ने निम्नलिखित अंतिम राय दी:-

"1. अदालत की राय है कि SS33900K 2/Lt परमदीप सिंहof 503 Asc। वह 27 नवंबर, 1989 को हिल ड्राइविंगटेस्ट पास करने के बाद वाहन को बोना f de ड्यूटी पर चला रहा था।

2) 2/lt परमदीप सिंहके पास MH ड्राइविंग लाइसेंस है: और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस।

3) दुर्घटना अचानक ब्रेक की विफलता के कारण हुई और किसी भी शरीर को दोषी नहीं ठहराया जाना है।

4) SS33900K 2/Li परमदीप सिंहके कारण होने वाली चोट क्षेत्र में ML सेवा के लिए जिम्मेदार है।

5) रु। 17266.00 राज्य द्वारा वहन किया जाना है।

6)) कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की राय सामान्य अधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 3 INF डिवीजन को कमांडिंग की थी:--

"एसएस33900K 2nd Lt परमदीप सिंहको FD क्षेत्र में ML सेवा के लिए जिम्मेदार होने के कारण चोट लगी।"

7)) कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अलावा, -फॉर्म "IAFY-2008" को भी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से तैयार किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सैन्य सेवा के कारण होने वाली चोट की घोषणा की गई थी।

8)) याचिकाकर्ताकमांड अस्पताल में भर्ती रहे। हेडक्वार्टरवेस्टर्नकमांड, चंडीमंदिर15 मार्च, 1990 तक और 15 मार्च, 1990 से 3 0 अप्रैल, 1990 तक बीमार छुट्टी पर रहा। उनके निर्वहन पर, याचिकाकर्ता की जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई और उन्हें मेडिकल श्रेणी SHA (यू) में रखा गया (यू) T-24) P d। आगे उन्हें अंतिम चिकित्सा श्रेणी में अपने प्लेसमेंट के लिए फ्रेशमेडिकल बोर्ड से गुजरने की सलाह दी गई।

9)) 15 अक्टूबर, 1990 को, एक और मेडिकल बोर्ड बुलाई गई थी, 'याचिकाकर्ता को मेडिकल श्रेणी SIII A (U) (स्थायी) PE में रखा गया था, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य बना रहा था। हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता को गतिहीन/हल्के कर्तव्यों के लिए फिट होने की सिफारिश की और क्षेत्र क्षेत्र और उच्च ऊंचाई में कर्तव्यों के लिए अनफिट किया। याचिकाकर्ता, जो एक लघु सेवा कमीशन अधिकारी था, को एनी में स्थायी आयोग के लिए डिस-एंटिटेड घोषित किया गया था। llie याचिकाकर्ता ने इस तरह के विस्तार के लिए पात्र होने का दावा करने वाली सेवा के विस्तार के लिए चुना। हालांकि, याचिकाकर्ता को 11 मार्च, 1994 को सेवा से छुट्टी और रिलीज़ किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने 70%पर याचिकाकर्ता की विकलांगता का आकलन किया। जैसा कि 20 अक्टूबर, 1993 (अनुलग्नक पी -2) के रिलीजऑर्डर से स्पष्ट है।

(११) उपरोक्त आदेश याचिका में चुनौती के विषय में हैं। प्रेसैंनल

(१२) भारत के संघ ने अपने अस्वीकरण में वर्तमान रिटd ने डिस्चार्ज के आदेश को सही ठहराने का प्रयास किया, जैसा कि विस्तार करने से इनकार कर दिया गया था? "इस आधार पर सेवा कार्यकाल कि याचिकाकर्ता ने एक दुर्घटना में एनी वाहन के दौरान चोट लगने के दौरान चोट लगी थी। यह आगे कहा गया है कि दुर्घटना अति-गति और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई, जिसके लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ वाहन को नुकसान की लागत का 15% की वसूली के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता था। उत्तरदाताओं ने सेवा के निर्वहन को भी पांच साल की अपनी संविदात्मक अवधि की समाप्ति के रूप में संदर्भित किया।

(13) विकलांगता पेंशन विनियमन के तहत अनुमेय है 173 की सेना पेंशन नियमों को परिशिष्ट के साथ पढ़ा गया - II।

(१४) ये प्रावधान यहाँ उद्धृत किए गए हैं:-

"नियम 173:

जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, विकलांगता पेंशन एक ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है, जिसे विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य कर दिया जाता है, जो कि सैन्य सेवा द्वारा जिम्मेदार या बढ़ाया जाता है और इसका मूल्यांकन अल20% या उससे अधिक है।

Cpiesl ionsचाहे विकलांगता जिम्मेदार है या सैन्य सेवा द्वारा उत्तेजित है, वह परिशिष्ट -11 में नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा।

परिशिष्ट II (नियम 2}

2टेबलमेन, या एक सेवा ने इसे प्रदान किया। "हॉल को सैन्य सेरफ्रे के कारण स्वीकार किया जाना चाहिए:-

(ए)डब्ल्यूडिसेबलमेंटएक घावचोट या बीमारी है

सैन्य सेवा के दौरान मिलहरीसेनबी और उलेओल के लिए पतले '

(१५) पूर्वोक्त नियमों के तहत, विकलांगता पेंशन एक व्यक्ति के लिए देय हो जाती है, जिसे 20% या अधिक विकलांगता के साथ सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य किया जाता है। परिशिष्ट- II को सैन्य सेवा के कारण चोट या बीमारी के कारण विकलांगता को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है या सैन्य सेवा के दौरान पहले या उत्पन्न होने के कारण अस्तित्व में है और इस तरह से उत्तेजित रहता है।

(16)थकाऊ आदेश (अनुलग्नक पी -3), संचार 11 दिसंबर दिसंबर। 1996, हालांकि, इस तरह की पेंशन याचिकाकर्ता को इस आधार पर इस बात से इनकार करता है कि चोट सैन्य सेवा द्वारा नहीं और न ही बढ़ी है। यह संचार भारत सरकार द्वारा इस तरह की राय के लिए किसी भी आधार का संकेत नहीं देता है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और मेडिकलरिलीज बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत लगता है।

(17) उत्तरदाताओं ने कैजुअल्टीपेंशनरीअवार्ड्स, १ ९ २ के लिए अधिकार नियमों को भी सूचित किया है। इन नियमों को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित किया गया था और समय -समय पर संशोधन किया गया है। नियमों का विचाराधीन मुद्दे पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है।

(१8) इन नियमों का प्रासंगिक अर्क यहाँ देखा गया:

(19) एंटाइटेलमेंट नियम नीचे दिए गए हैं, जो सेवा कर्मियों के लिए लागू हैं, जो जे सेंट जनवरी 1982 को या उसके बाद गैर-प्रभावी हो जाते हैं। 1 जनवरी 1982 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले मामलों को इन नियमों के तहत माना जा सकता है बशर्ते कि ऐसा मामला अभी भी बकाया है इन नियमों के मुद्दे की तारीख पर। यह परिभाषित करने के उद्देश्य से कि किसी मामले को बकाया माना जाएगा या नहीं। यह स्पष्ट कर सकता है कि जहां इस तरह के मामले को पहले से ही शुरुआती चरण में भी तय किया गया है, वही वह वैसा ही होगा जैसा कि तय किया गया था। ऐसे मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा। इन नियमों को गाइड टूमेडिकलऑफिसर (सैन्य पेंशन) 1980 के साथ संयोजन में पढ़ा जाएगा; के रूप में संशोधन।

(४) विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए सेवा से अमान्य होना एक आवश्यक शर्त है। एक व्यक्ति जो अपनी रिहाई के समय (वह नियम जारी करता है, एक कम चिकित्सा हैया आश्रय नियुक्ति प्रदान की जा सकती है, जैसा कि वैकल्पिक रोजगार में बनाए रखने वाले लोगों के रूप में घूंघट है, लेकिन उनकी सगाई के पूरा होने से पहले छुट्टी दे दी जाती है, जिसे सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।
6 मृत्यु के विकलांगता को स्वीकार किया जाएगा क्योंकि सैन्य सेवा के कारण यह उचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है:
(ए) अक्षम एक घाव, चोट या बीमारी के कारण है-
(i) सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है, या
(ii) सैन्य सेवा के दौरान इससे पहले या उत्पन्न हुआ था और इस तरह से बढ़ गया है। इसमें एक विकलांगता की शुरुआत के पूर्ववर्ती/जल्दबाजी में भी शामिल होगा।
8. यदि मृत्यु/विकलांगता और सैन्य सेवा के बीच आकस्मिक संबंध उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो अट्रैक्टिविटी/एग्रेटिवेशन को स्वीकार किया जाएगा।

सबूत-
एच दावेदार को अधिकारों की शर्तों को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वह/वह किसी भी संदेह का लाभ प्राप्त करेगा। इस लाभ को और अधिक ड्यूटी दी

जाएगी, 'फील्ड/एफ़्लोट सेवा मामलों में कोई चैमनिस नहीं।सशस्त्र के सिलनेलियोअनुशासनात्मक कोड पर सामनेओज़? सीएम कार्य या एक कार्य जोड़ें, आंदोलन के मोड के एक और स्थान के लिए ड्यूटी के एक अपराध के लिए एक अपराध के अपराध का गठन करने में विफलता।पूर्ववत करें

चोटों

13. दुर्घटनाओं या चोटों के संबंध में, निम्नलिखित नियम वह देखेंगे:-

(ए) जब आदमी को "ड्यूटी पर" परिभाषित किया जाता है, तब तक चोटें लगती हैं, माना जाता है कि IOसैन्य सेवा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन गंभीर लापरवाही/ कदाचार के कारण मामलों में चोटें विकलांगता पेंशन को कम करने के सवाल पर विचार करेंगे।

(बी) विधिवत पर स्व-पीड़ित चोटों के मामलों में, जब तक कि यह स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि सेवा कारक ऐसे मामलों में इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं थे, जहां ऑलरीहुलैबिलिटी को स्वीकार किया जाता है, विकलांगता पेंशन के अनुदान का सवाल भरा हुआ है या एएल कम हो गया है। वह विचार करेगा।

आकलन

22) विकलांगता की डिग्री का आकलन पूरी तरह से चिकित्सा निर्णय का मामला है और चिकित्सा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सैन्य बलों के एक सदस्य की सेवा/कर्तव्य के कारण विकलांगता की डिग्री का आकलन सदस्य की शर्तों के बीच तुलना करके और एक ही उम्र और सेक्स के एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति के बीच तुलना करके किया जाएगा। अपने स्वयं के या किसी अन्य विशिष्ट व्यापार या व्यवसाय में, और किसी भी व्यक्तिगत कारक या बाहरी परिस्थितियों के प्रभावों को ध्यान में रखे बिना, अपनी अक्षम स्थिति में सदस्य की कमाई क्षमता को ध्यान में रखे बिना। "

(19) पूर्वोक्त नियमों को आगे बढ़ाया गया था, जो कि एडजुटेंट जनरल ब्रांचवीडलेटर से जारी किए गए निर्देशों के बाद 29 सितंबर, 2006 को।

"कार्मिक सेवा निदेशालय ने 30 अगस्त, 2006 को डीईएफ और सरकारी आदेशों के मिन के साथ एक मामला उठाया था, जिसमें विकलांगों के लिए

एसएससीओएस/ईसीओ द्वारा प्रदान की गई पूर्ण सेवा के लिए सेवा तत्व को अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उन अधिकारियों के लिए सैन्य सेवा जिन्हें पत्र के मुद्दे पर या बाद में सेवा से जारी किया गया था। सेवानवंबर। 1977. 1965 का विशेष सेना अनुदेश संख्या 6/एस और इस मंत्रालय का पत्र संख्या F2K 795/74/पेन-सी। दिनांक 30 नवंबर। 1977 उस हद तक संशोधित एलओ को खड़ा करेगा।

इन आदेशों के मुद्दे के डेल से पहले सेवानिवृत्त गैर-नियमित कमीशन अधिकारियों के संबंध में विकलांगता पेंशन का सेवा तत्व इन आदेशों के अनुसार संभावित रूप से संशोधित किया जाएगा। जो इस पत्र के मुद्दे की तारीख पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।

(२१) उत्तरदाताओं का उत्तर इस उत्तर में है कि दुर्घटना याचिकाकर्ता की लापरवाही के कारण हुई थी, जबकि एनी वाहन को चलाते हुए, किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड से पुष्टि नहीं की गई है, इसके विपरीत, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत, अंतिम राय अदालत और सामान्य अधिकारी की टिप्पणियों की कमान, स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी लापरवाही की अनुपस्थिति का संकेत देती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के स्पष्ट और श्रेणीबद्ध निष्कर्षों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास पहाड़ी क्षेत्रों पर ड्राइव करने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। वह एक आधिकारिक कर्तव्य के लिए विस्तृत था। ब्रेक विफलता के कारण दुर्घटना हुई। अदालत के अंतिम फैसले ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता द्वारा निरंतर चोट सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है। वाहन को होने वाली क्षति भी राज्य द्वारा वहन की जानी है। उत्तर में गंजे बयान को छोड़कर कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्घटना के लिए कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी या उसकी लापरवाही के कारण भी ऐसा था। न ही याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पाया गया। याचिकाकर्ता को रिलीज़मेडिकल बोर्ड के ओपियन के अनुसार छुट्टी दे दी गई है, जो उसे क्षेत्र क्षेत्र में सैन्य सेवा के लिए अनफिट कर रही है। उत्तरदाताओं का स्टैंड कि याचिकाकर्ता का निर्वहन सेवा के अपने कार्यकाल को समाप्त करने के कारण है, वह एक लघु सेवा कमीशन अधिकारी होने के नाते, सक्षम प्राधिकारी के किसी भी निर्णय द्वारा समर्थित नहीं है। यह अफसोस का एक मैटसी है कि इस तरह के स्टैंड को उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया है

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की राय को समाप्त करें, जैसा कि उनके ओ "एनरिकोईयू ए। इस मामले में ओलअमरनाथ जीता या भारत और अन्य, (2), जहां वह अदालत में, के रूप में आयोजित किया गया था।

"एक बार जब यह प्रमाण पत्र अपीलकर्ता के पक्ष में जारी किया गया था, तो उसे प्राप्त करने का हकदार थाविकलांगता पेंशन, यह लाभ नियंत्रक द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता था

रक्षा खाते (पी), इलाहाबाद अपीलीयमेडिकल बोर्ड के बिना अपने दम पर

कानून के अनुसार। अपीलकर्ता के दावे को खारिज करते हुए प्रदर्शनी डी। अंतर्गतआर पंजाब अनहरीआना

2010 (2)25 जून के पिछले 10 साल की अवधि। 1988 और विकलांगता कम है कि 20%। यह आदेश के पारित होने से पहले अपीलकर्ता को कभी नहीं रखा गया था। यदि अपीलकर्ता विकलांगता प्रमाणपत्र पूर्व की ताकत पर नियमों के अनुसार लाभ का हकदार था। PI. अपीलार्थी को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और अपीलकर्ता को उचित अवसर देने के बाद उसी का विभाजन नहीं किया जा सकता है जो वर्तमान मामले में स्वीकार नहीं किया गया है। इस मुख्य मुद्दे के लिए कोरोलरी यह है कि क्या रक्षा खातों के नियंत्रक (पी), इलाहाबाद के नियंत्रक को यह मानने में उचित ठहराया गया था कि अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, नियमों के तहत इसमें निहित नहीं है। प्रासंगिक / ucsऔर इंस्टीनेटआयनों के तहत, उत्तरदाताओं के पास प्राधिकरण टन mtfe cmअपीलीय बोर्ड है और पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा निष्कर्षों I / II} सीडी को परेशान करता है जो फिर से 11 नहीं था। प्रासंगिक नियमों के लिए Ecourseऔर ऑब्जेक्ट को पाइलिन। "

(२४) माननीय बीएलसी दिल्ली के एक अन्य डिवीजन बेंच निर्णय में आई लीघ कोर्ट ने बताया

2006 (4) एससीटी 545, निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:-

(२५) इसी तरह, ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की किसी भी चोट के संबंध में एक अदालत की जांच की गई है और यह कमांडिंगऑफिसर द्वारा आयोजित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगी चोट सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार थी और उस व्यक्ति को रखा गया था। रक्षा खातों के मुख्य नियंत्रक (पेंशन) द्वारा पारित कम

चिकित्सा श्रेणी के आदेश संक्षेप में प्रक्रिया का पालन किए बिना विकलांगता के दावे को खारिज कर देते हैं, जैसा कि श्री भगवान के मामले (सुप्रा) में उल्लेख किया गया है, दुर्बलता से पीड़ित है और उसी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। '

(२६) उत्तरदाताओं का स्टैंड कि याचिकाकर्ता को उनके कार्यकाल की समाप्ति के कारण छुट्टी दे दी गई थी और इस प्रकार, विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं हैं, को भी हकदार नियमों और विनियमन ५३ के नियम ४ के मद्देनजर खारिज कर दिया जाना है। सेना के नियम। सेना विनियमन के विनियमन 53 के तहत प्रदान करता है:
"53. अधिकारी अनिवार्य रूप से उम्र के आधार पर या कार्यकाल के पूरा होने पर सेवानिवृत्त हुए। एक अधिकारी अनिवार्य रूप से उम्र के आधार पर या कार्यकाल के पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो गया, अगर सैन्य सेवा द्वारा सेवानिवृत्त या बढ़े हुए विकलांगता से सेवानिवृत्ति पर पीड़ित और सेवा चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया। राष्ट्रपति के विवेक पर, सेवानिवृत्त पेंशन के अलावा, एक विकलांगता तत्व के अलावा, वह विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो गए थे, सेवानिवृत्ति के समय विकलांगता की स्वीकृत डिग्री के अनुसार। "

(27) पूर्वोक्तविनियमनक्लीटिटी यह प्रदान करता है कि जहां एक अधिकारी कार्यकाल के पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो जाता है और वह सैन्य सेवा के कारण किसी भी विकलांगता से पीड़ित या बढ़ रहा है और सेवा चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया है। अध्यक्ष। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को उनके कार्यकाल के पूरा होने पर छुट्टी नहीं दी गई थी। रिकॉर्ड पर रखी गई पूरी सामग्री इस तथ्य के लिए सूचक है कि याचिकाकर्ता की रिहाई उसके कार्यकाल की समाप्ति के कारण नहीं थी, लेकिन विकलांगता के कारण उसे कम चिकित्सा श्रेणी में रखकर उसे क्षेत्र क्षेत्र में सैन्य सेवा के लिए अनफिट पाती है। यह इन परिस्थितियों में है कि याचिकाकर्ता ने गतिहीन/प्रकाश शुल्क पर सेवा में विस्तार का दावा किया है, जो उनकी प्रार्थनाओं में से एक है। विनियमन 53 के संदर्भ में, एक व्यक्ति जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होता है या कार्यकाल के पूरा होने पर जारी करता है

सैन्य ^ ^के लिए या बढ़े हुए विकलांगता से
1 "। , स्पष्ट रूप से यह प्रदान करता है कि विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए सेवा से अमान्य होना आवश्यक शर्त है। मैं उसे याचिकाकर्ता को कम चिकित्सा श्रेणी

में रखकर विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया है। यूआईएस विकलांगता का मूल्यांकन 70% पर किया गया है (वह चिकित्सा जारी करता है। बोर्ड, विकलांगता पेंशन के लिए उनके दावे को विवादित नहीं किया जा सकता है।

(२8) हताहत पेंशन के लिए हकदार पेंशन अवाड्र्स, १ ९ २। जबकि नियम 4 विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में सेवा से अमान्य होने से संबंधित है। नियम 6 सैन्य सेवा के कारण घाव की चोट के कारण विकलांगता से संबंधित है। पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि भले ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित के रूप में विकलांगता और मिलिटेटी सेवा के बीच एक आकस्मिक संबंध हो, विकलांगता पेंशन देय है। नियम 9 अधिकारियों को यह स्थापित करने के लिए सबूत के स्थान पर है कि विकलांगता सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(29) उपरोक्त उद्धृत नियमों और विनियमों के संयोजन से पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि दावेदार को हकदारता की शर्तों को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, बल्कि लाभ को उदारतापूर्वक और संदेह के मामले में लाभ दिया जाना चाहिए। दावेदार के पास जाना चाहिए।

(३०) वर्तमान मामले में, यहां तक कि एक संदेह का भी कोई सवाल नहीं है, बल्कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के स्पष्ट निष्कर्षों से यह स्थापित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निरंतर चोट सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है। यहां तक कि पूर्वोक्त 1982 के पुरस्कारों के नियम 12 के तहत परिभाषित कर्तव्य भी वर्तमान फूतेयाचिकाकर्ता में आकर्षित किया गया है, जब उन्हें चोट लगी थी। कोवकमस्टेंस को देखते हुए, याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन का हकदार है।इन सर्विस, हालांकि, अकाउंट फ़ोमेंट्स के दौरान, सेवा में विस्तार के लिए दावे को इस याचिका की संख्या की संख्या के लिए छोड़ दिया गया था।
अनुमत। उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है
एक अवधि तीन महीने। वहाँ, मामला "वर्षों से पहले एई बकाया राशि को रिट याचिका में तीन तक सीमित कर दिया जाएगा।

समक्ष-एम , कुमार और जसवन्त सिंह .एम .माननीय न्यायमूर्ति

मैसर्स हिंदुस्तान पॉलीपैक्सपेलिशनर-

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी .पी.डब्ल्यू.1998 का क्रमांक 14411

2009 दिसंबर 14

भारत का संविधान,1950226 अनुच्छेद--हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम ,1973- .एस13 ,नियम (दूसरा संशोधन) हरियाणा सामान्य बिक्री कर-बी-1989- .आरआई28ए) 2एलएलएससी अनुसूचीके अनुसार उद्योगों की -बिक्री कर छूट का दावा-(नकारात्मक सूची में आने वाले याचिकाकर्ता को खारिजकरते हुए -एच एल एस सीने याचिकाकर्ता की अपील को भी खारिज कर दिया 28 नियमों के नियम -A के उप नियम 4 (एमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या तारीख से कर (पात्रता प्रमाणपत्र जार/छूट का लाभ का दावा कर सकता है। उसके विकल्प के अनुसार छूटी करना 4 ए के उपनियम28 नियम - ऐसा विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं है -(एके प्रावधान (उपनियम - से की जाती है 3 खासकर जब प्रावधान की तुलना उपनियम ,अनिवार्य नहीं हैं के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि एक विकल्प किसी पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा कर छूट 3 या स्थगन का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा याचिकाकर्ता की इकाई उस तारीख को - सभी प्रकार से पात्र है जब पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया था ताकि लाभ उठाया जा सके। बिक्री कर छूट का लाभछूट /छूट या तो पात्रता ,इसलिए , प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दी जा सकती है

केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने नकारात्मक सूची में होने पर वाणिज्यिक उत्पादन की - इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह पात ,तारीख का विकल्प चुना है ैरताछूट प्रमाणपत्र / - जारी करने की तारीख से प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि नियम अनिवार्य नहीं है 'एलएलएससीछूट प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से बिक्री कर से छूट देने के /पात्रता ' जब याचिकाकर्ता को रख ,लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य हैंने पर रोक है ,याचिका स्वीकार की गई-उद्योग को नकारात्मक सूची से हटाया गया ^ द्वारा पारित आदेशों को कानून की नजर में अस्थिर 'एचएलएससी' और 'एलएलएससी' माना गया और रद्द कर दिया गया।

हेहल4 ए के उप नियम28 नियमों के नियम ,(एमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि (याचिकाकर्ता अपने विकल्प के अनुसार या तो वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से या छूट पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से कर छूट का लाभ का दावा कर सकता है। . इसका दावा याचिकाकर्ता द्वारा हमेशा या तो ^उपरोक्त विकल्प अपरिवर्तनीय नहीं है छूट प्रमाण पत्र जारी होने/अधिकार की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से किया जा सकता है। नियमों के नियम 4 ए के उप नियम 28(एके प्रावधान विशेष रूप (से की जाती है तो 3 नियम-ए के उप28 से अनिवार्य नहीं हैं जब प्रावधान की तुलना नियम के अवलोकन से पता चलता है कि एक पात्र औद्योग 3 नियम-उपिक इकाई द्वारा कर छूट या कटौती का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। नियम के निर्माता ने आगामी उप4 नियम-(एमें अनिवार्य भाषा का उपयोग नहीं किया है और यह प्रावधान (किया है कि एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प को अंतिम माना जाएगा।

19 पैरा))

इसके अलावायह माना गया कि याचिकाकर्ता की इकाई उस तारीख को सभी प्रकार से पात्र ,

है जब बिक्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन दायर किया गया था। तदनुसारछूट प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से या /छूट या तो पात्रता , वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दी जा सकती है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने इसका ,जब वह नकारात्मक सूची में थी ,वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख को चुना है छूट प्रमाणपत्र/मतलब यह नहीं होगा कि इसे पात्रता जारी करने की तारीख से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नियम अनिवार्य नहीं है। इसलिएछूट प्रमाणपत्र /पात्रता 'एलएलएससी' , जारी होने की तारीख से बिक्री कर से छूट देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार जब याचिकाकर्ता के उद्योग को नकारात्मक ,करने के लिए बाध्य था सूची में रखने की बाधा हटा दी गई थी। यह माना जाता है कि ,अक्टूबर 28 द्वारा 'एलएलएससी'1994 को पारित आदेश और ,अगस्त 5 एचएलएससी द्वारा'1995 को पारित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

20 पैरा))

याचिकाकर्ता के वकील संदीप गोयल।

उत्तरदाताओं की ओर से आरहरियाणा। ,डीएजी ,शर्मा .डी .

एम.जे ,कुमार .एम .

संविधान के अनुच्छेद के तहत दायर यह याचिका निचले स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी 226 'टीजेएलएससी ,संक्षिप्तता के लिए)) द्वारा पारित ,अक्टूबर 281994 -पी)10के (जिसमें याचिकाकर्ता के बिक्री कर छूट के दावे को इस आधार पर ,आदेश को चुनौती देती है खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की इकाई ,फरवरी 111994 से पहले और उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभागफरवरी को जारी अधिसूचना के 11 हरियाणा द्वारा , 1994 मद्देनजर उत्पादन में लग गई थी।(पी-9(, यह उक्त लाभ के लिए योग्य नहीं है।

एलएलएससी द्वारा यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता की इकाई ,फरवरी 111994 से पहले हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम ,1975 की (नियम ,संक्षिप्तता के लिए) अनुसूची॥। में संलग्न उद्योगों की नकारात्मक सूची में थी। उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी 'एचएलएससी' ,संक्षिप्तता के लिए)) द्वारा पारित आदेश दिनांक ,अगस्त 51998 -पी) 12) को भी चुनौती दी गई है ,अक्टूबर 28 जिसमें ,1994 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष में हरियाणा राज्य ने एक औद्योगिक 1988 ,अप्रैल 1 जो ,नीति बनाई और कुछ उद्योगों को1988 के बाद स्थापित किए गए थे , उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी। चूंकि हरियाणा ,सामान्य बिक्री कर अधिनियम1973 'एचजीएसटी अधिनियम ,संक्षेप में)) में छूट का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थाप्रतिवादी राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ान ,इसलिए ,े की दृष्टि से13 एचजीएसटी में धारा ,-बी शामिल की गई थी। के हरियाणा अधिनियम 1988 हयाना राज्य को उद्योग के ,साथ-अन्य बातों के साथ ,के तहत अधिनियम 26 संख्या किसी भी वर्ग को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देने का म 17 अधिकार देता है।ई ,1989 को ,हरियाणा राज्य ने नियमों में संशोधन करते हुए , ,नियम (द्वितीय संशोधन) हरियाणा सामान्य बिक्री कर1989 को अधिसूचित किया। मौजूदा नियमों के अध्याय IV के बाद अध्याय ,IV-ए को कर के भुगतान से छूटस्थगन के / अवधि और अन्य शर्तों के शीर ,लिए उद्योगों के वर्ग्षक के साथ जोड़ा गया था। उक्त अध्याय में नियम ए को भी नियमों में शामिल किया गया है। नियमों का नियम28)ए282 ('संचालित अवधि ,'योग्य औद्योगिक इकाई' ,'नई औद्योगिक इकाई' ,' 'छूट' ,'पात्रता प्रमाण पत्र' ,'मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग ,'स्क्रीनिंग समिति' सहित विभिन्न अभिव्यक्तियों के अर्थ को परिभाषित करता है। प्रमाणपत्रप्रेरक बिक्री कर ,'

जो तत्काल याचिका में उठाए गए मुद्दों के प्रयोजनों के ,'नकारात्मक सूची' और 'दायित्व)ए28 लिए प्रासंगिक हैं। नियम4कर छूट या स्थगन के लाभ से संबंधित है और प्रावधान (करता है कि यहछूट या पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई को दिया जाएगा। वर्ष से वर्ष तक की सीमा तक और अवधि तक कार बी 'ए' ज़ोन .विभिन्न जोन . के अंतर्गत आने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिए कर छूट की मात्रा और अवधि का नियम ,विविधीकरण का इरादा रखते हैं/ऐसी इकाइयों से संबंधित जो विस्तार ,विवरण)ए284)ए28 नियम . में दी गई है। (5इस नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ( )ए28 एक विस्तृत प्रक्रियाबताता है जबकि नियम7साल दर साल आधार पर छूट (प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करता ह ै। नियम)ए282)(7) खंड (0-के तहत अनुसूची (3 में उद्योगोंउद्योगों के वर्ग का विवरण /) ए के उपनियम28 जो किनकारात्मक सूचीनियमों के नियम ,दिया गया है2 के खंड (समय पर उन उद्योगों की सूची जारी -का प्रभाव यह है कि अब उद्योग विभाग समय (ओ) करता है जो बिक्री की प्रकृत ि में प्रोत्साहन अनुदान के हकदार नहीं होंगे। कर छूट ,स्थगन/ ,पूंजी निवेश सब्सिडी और बिजली शुल्क आदि। ऐसी नकारात्मक सूची के आधार पर हरियाणा राज्य की विभिन्न एजेंसियां उन औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर कार्रवाई करती ,जनवरी 11 हैं जो प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहती हैं।1991 को उद्योग विभाग ने उन उद्योगों की श्रेणी को अधिसूचित किया जो -पी) की औद्योगिक नीति 19881के तहत पूंजी निवेश (सब्सिडी के अनुदान के लिए पात्र नहीं थे। यहां यह ध्यान देना उचित है कि नियमों के ,जनवरी 3 उद्योग विभाग ने ,ए की घोषणा के बाद 28 नियम1 ,जून 19 और 991 1991 को दो नकारात्मक सूचियां जारी कीं। इसमें उन उद्योगों की श्रेणी शामिल थी जो बिक्री कर छूट अनुदान के लिए अयोग्य थे। स्थगन.

वर्ष ,आई लारियाना राज्य द्वारा एक अन्य औद्योगिक नीति तैयार की गई ,में 1992

' ,जिसका नाम था1992 की नई औद्योगिक नीतिकी नई औद्योगिक नीति के 1992 ।' 1992 मार्च को अधिसूचित की गई थी। 9 तहत उद्योगों के वर्ग की एक नकारात्मक सूची, जिसने पिछली नकारात्मक सूचियों -पी)2 .मई को 25 को हटा दिया है। (1993 . हरियाणा राज्य के उद्योग विभाग ने एक और अधिसूचना जारी कर सूचित किया है कि उल्लिखित उद्योगों को नकारात्मक सूची में रखा गया है और वे बिक्री कर छूटस्थगन सहित / किसी भी प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे। आगे यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि और उसमें मौजूद सूची का ग्रामीण उद्योग योजना ^उक्त अधिसूचना डेटाकॉल से प्रभावी होगी - पी)3के तहत स (्थापित औद्योगिक पर कोई लागू नहीं होगा।याचिकाकर्ताकीओरसेदावाकियागयाहैकिअधिसूचना 25 मईकीहै .1993 नेनकारात्मकसूचीकोहटादियाहैजिसे 9 मार्चकोअधिसूचितकियागयाथा। 1992. इसपड़ावपरयहउल्लेखकरनाउचितनहींहैकियाचिकाकर्ताएकसाझेदारीफर्महैजोT।DPE/PP बुनेहुएबोरेऔरपॉलिथीनबैगऔरशीटकेविनिर्माणव्यवसायमेंलगीहुईहै।

यहदावाकियागयाहैकियाचिकाकर्ताकीविनिर्माणइकाईको 25 मई ,1993 सेनकारात्मकसूचीसेबाहरकरदियागयाथा। दूसरेशब्दोंमें ,याचिकाकर्ताकेउद्योग , जोपॉलिथीनबैगऔरशीटकानिर्माणकररहेथे ,उन्हेंराज्यद्वारापात्रबनादियागयाथा। 1992 कीनईऔद्योगिकनीतिकेतहतबिक्रीकरछूट/स्थगनसहितप्रोत्साहनदेनेकेलिए 25 मई 1993 सेहवानाकी।

उद्योगविभागद्वाराजारी 25 मई ,1993 कीअधिसूचनाकेअनुसरणमें ,उत्पादशुल्कऔरकराधानविभाग-प्रतिवादीनंबर 1 नेनियमोंकीअनुसूची-III और 13 अक्टूबरकीएकअधिसूचनामेंसंशोधनकेलिएप्रक्रियाशुरूकी। 1993मेंअनुसूची-III मेंसंशोधनहेतुप्रारूपनियमोंकाप्रकाशनजारीकियागयातथाआपत्तियांअथवासुझावआमंत्रितकियेगये) पी-4 ।(उल्लेखनीयरूपसे ,

मसौदानियमोंमेंपॉलिथीनबैगऔरशीट्सकेनिर्माणमेंलगेउद्योगोंकेवर्गकोशामिलनहींकियागयाथा ,
जैसेकियाचिकाकर्ताकीइकाईकोनकारात्मकसूचीमेंरखागयाथा। 13अक्टूबर ,1993
कीअधिसूचनामेंअनुसूची-III में 25 मईसेपुनःप्रभावीसंशोधनकरनेकाइरादाभीदर्शायागयाथा। 1993
(अर्थात्उद्योगविभागद्वाराजारीअधिसूचनादिनांक 25 मई 1993 केप्रवर्तनकादिन।(
याचिकाकर्तानेदावाकियाहैकि 1992
कीनईऔद्योगिकनीतिकेतहतघोषितप्रोत्साहनोंकीउपलब्धतासेप्रेरितहोकर ,
याचिकाकर्तानेकमलमेंएकऔद्योगिकइकाईस्थापितकरनेकेबारेमेंभीसोचाऔरएकविस्तृतपरियोजनारि
पोर्टबनानेकेबादसंबंधितअधिकारियोंकोअपनेआवेदनप्रस्तुतकिए।
याचिकाकर्ताकोउत्पादनशुरूहोनेकीतारीखयानी 20 दिसंबर ,1993)पी-5 (
सेबिजलीशुल्कसेछूटदीगईथी ,उसकेद्वाराखरीदेगएजेनरेटिंगसेट) पी-6(,
औद्योगिकएस्टेटमेंएकऔद्योगिकभूखंडपरपूंजीगतसब्सिडीदीगईथी। कमलको) पी-7 (
भीआवंटितकियागयाऔरलगभगरु .उद्योगचलानेकेलिए 24 सितंबर 1993
कोहरियाणावित्तीयनिगमद्वारा 10 लाखरुपयेभीदिएगए) पी-8 ।(
यहदावाकियागयाहैकियाचिकाकर्ताकोउपरोक्तसभीलाभमहाप्रबंधकद्वाराकीगईसिफारिशोंकेआधारपरदि
एगएथे। जिलाउद्योगकेंद्र .कमल-प्रतिवादीसंख्या4 . जिन्होंने 25
मईकीअधिसूचनाकेअनुसारयाचिकाकर्ताकेमामलेकीसिफारिशकीथी। 1993और 13 अक्टूबर ,1993
)पी-3 औरपी-4 ।(
इसकेबादयाचिकाकर्तानेकमलमेंअपनीऔद्योगिकइकाईस्थापितकीऔरपंजीकरणकेलिएप्रतिवादीनंबर
4केपासआवेदनकियाएकलघुऔद्योगिकइकाईकेरूपमें। इसेलघुउद्योगसवारीपंजीकरणसंख्या
050050o786, दिनांक 24 अगस्तकेरूपमेंअनंतिमरूपसेपंजीकृतकियागयाथा। [993 इसकेबादइसे
27दिसंबरकोनियमितपंजीकरणसंख्या 050526786 भीप्रदानकियागया। 1993प्रतिवादीसंख्या 4
द्वारा। याचिकाकर्ताकीऔद्योगिकइकाईमेंवाणिज्यिकउत्पादन 20 दिसंबर ,1993 कोशुरूहुआ।

11फरवरीको .1994को याचिकाकर्तानेपात्रताप्रमाणपत्रप्रदानकरनेकेलिएप्रतिवादीसंख्या 4 कोनिर्धारितफॉर्मएसटी- 70 मेंआवेदनकिया ,जिससेवहनियम 28एकेतहतबिक्रीकरछूटकालाभउठासके।

नियमजोदिनांकसे 90 दिनोंकीनिर्धारितअवधिकेभीतरथेव्यावसायिकउत्पादनका .11 फरवरीको . 1994 मेंही ,उत्पादशुल्कएवंकराधानविभाग , हरियाणानेअनुसूचीमेंसंशोधनकरतेहुएएकअधिसूचनाजारीकी-संभावितरूपसे 11 फरवरी ,1994 सेप्रभावी) पी9-)। नतीजतनपॉलिथीनबैगऔरशीटबनानेवालेउद्योगोंकेवर्गकोअनुसूची-III मेंनिहितनकारात्मकसूचीसेबाहरकरदियागयाहै।

28अक्टूबर ,1994 को ,प्रतिवादीनंबर 4 नेयाचिकाकर्ताकोसूचितकियाकिबिक्रीकरछूटदेनेकेउसकेआवेदनपर' एलएलएससी ' नेविचारकियाऔरखारिजकरदियाक्योंकियाचिकाकर्ताकीऔद्योगिकइकाईअनुसूची-III केअनुसारउद्योगोंकीनकारात्मकसूचीमेंआगईथी। नियमोंके) P-10). 24 नवंबर ,1994 कोयाचिकाकर्ताने' एचएलएससी '(पी-11 (केसमक्ष 28 अक्टूबर ,1994 केआदेशकेखिलाफनियमोंकेनियम28 ए)5)(एफ (केतहतअपीलदायरकी। चारसालबाद , 'एचएलएससी 'ने 5 अगस्त ,1998)पी-12 (केआदेशकेजरिएअपीलखारिजकरदी। 'एचएलएससी ' कानिर्णययाचिकाकर्ताकेवकीलको 14 अक्टूबर ,1998 कोसूचितकियागया) पी-13।(

प्रतिवादीनंबर 1

द्वारादायरलिखितबयानमेंयहरुखअपनायागयाहैकिबिक्रीकरछूटकाप्रोत्साहनकेवलएकरियायतहैऔरयह याचिकाकर्ताकोकोईकानूनीरूपसेलागूकरनेयोग्यअधिकारप्रदाननहींकरताहै। 1

वह■बिक्रीकरभुगतानऔरवसूलीकेउद्देश्यसेउत्पादएवंकराधानविभागद्वाराजारीअधिसूचनाएंअंतिमहैं। यहप्रस्तुतकियागयाहैकिउत्पादशुल्कएवंकराधानविभागद्वाराजारीदिनांक 17 मई ,1989

कीअधिसूचनाअंतिमहैऔरवर्तमानमामलेपरलागूहै। याचिकाकर्ता अधिसूचना की 1994 फरवरी 11 ।थे आए में अस्तित्व जो है होती लागू पर उद्योगों उन यह क्योंकि होगी नहीं लागू पर मामले के यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू को दिसंबर 20 कियागया। के छूट से कर बिक्री ,प्रकार इस। था में सूची नकारात्मक यह समय उस और 1993 .अनुसार के अधिसूचना की मई 7 1 कि है गया कहा आगे। हैं नहीं पात्र लिए1989 के नियमों . ।है से अप्रैल 1 अवधि परिचालन की व्यक्ति वाले करने मांग की छूट कर बिक्री तहत के ए28 नियम 31 से 1988 मार्च तक .1997.1 कम के नियमों .अनुसूचि ।।। के अनुसार नकारात्मक सूची में शामिल उद्योग छूट के लाभ के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्ता फर्म पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माण में लगी हुई है हकदार का लाभ के छूट बिक्री याचिकाकर्ता तरह इस और है में सूची नकारात्मक जो , नहीं है। तदनुसारद्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन और अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है2 संख्या प्रतिवादी। क्रमशः *एचएलएससी' और ?. अलग एक पर तर्ज इसी भी द्वारा 4 और 3 ।है गया किया दायर बयान लिखित

याचिकाकर्ता के वकील श्री संदीप गोयल ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने घोषित में 1992 शीट और बैग पॉलिथीन में अनुसरण के रियायतों विभिन्न घोषित उसमें और नीति औद्योगिक नई वाणिज्यिक से दिसंबर 20 अनुसार के वकील विद्वान। थी की स्थापित इकाई औद्योगिक अपनी की द्वारा इसके और 1993 ।थी गई दी छूट से बिजली विधिवत इसे से तारीख की होने शुरू उत्पादन विभिन्न गए दिए में 10 पैरा के याचिका मैंने। गई दी भी सब्सिडी पर सेट जेनरेटिंग गए खरीदे औद्योगिक में एस्टेट औद्योगिक कि है दिया तर्क और है किया आकर्षित ध्यान हमारा ओर की कथनों .पी एनेक्सचर विवि को कमल। भी भूखंड7 और लगभग रुकिय आवंटित ऋण का .ा गया। औद्योगिक इकाई चलाने के लिए .पी) निगम वित्तीय हरियाणा रुपये लाख 108 थे गए दिए द्वारा (। थे गए किए जारी पर आधार के सिफारिश गई की द्वारा महाप्रबंधक को याचिकाकर्ता लाभ वे और

बिक और देने पत्र प्रमाण पात्रता ने याचिकाकर्ता बार एक ,इसलिए .केंद्र उद्योग जिला्री कर छूट का लाभ उठाने के लिए तब 1994 ।है किया आवेदन में 70 एसटी फॉर्म निर्धारित को फरवरी 11 ।को फरवरी 11 जब खासकर ,था नहीं कारण कोई का करने इनकार से लाभ पास के उत्तरदाताओं दिया हटा से सूची नकारात्मक को उद्योग संबंधित से निर्माण के शीट और बैग पॉलिथीन 1994 गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित होगा और

याचिकाकर्ता के वकील श्री संदीप गोयल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता जैसे पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माताओं को ,मई 251993 को औद्योगिक विभाग द्वारा नकारात्मक सूची से हटा दिया गया था। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग ने इसी तरह ,अक्टूबर 13 1993 -पी)4 आपत्तियां जिसमें ,है किया प्रकाशित को नियमों मसौदा से माध्यम के अधिसूचना की (शीट और बैग पॉलिथीन क्यों कि हैं गई की आमंत्रितके विनिर्माण उद्योगों को नकारात्मक सूची से बाहर नहीं किया जाए। ,मई 251993 से प्रभावी। हालाँकि ,11 फरवरी ,1994 की अधिसूचना -पी) 9 ,मई 25 यह। था गया दिया हटा से सूची नकारात्मक से रूप अवैध इसे द्वारा (1993 से लागू किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील के अनुसार याचिकाकर्ता ने ,फरवरी 111994 को ही एक आवेदन देकर नियम)ए285। थी की मांग की छूट भीतर के अवधि निर्दिष्ट की दिनों 90 से तारीख तहत के ( ) खंड के ए28 नियम अनुसार के वकील विद्वान .उत्पादन वाणिज्यिक2 परिचालन तहत के (ए)(,अप्रैल 1 अवधि1988 से ,मार्च 311997 है और नियमों के नियम 2 खंड के ए28(सी के अर्थ के (लिए के छूट भीतर के दिनों 90 के उत्पादन वाणिज्यिक हमेशा। है सकती हो इकाई नई एक भीतर ,दिसंबर 20 इकाई की याचिकाकर्ता कि है दिया तर्क उन्होंने। करें आवेदन1993 को वाणिज्यिक उत्पादन में चली गई थी। इसलिएद्वा याचिकाकर्ता ,रा ,फरवरी 111994 को दायर किया गया आवेदन दिनांक से नियमों के नियम) ए 285 वाणिज्यिक। था भीतर के दिनों 90 के अर्थ के (

28 द्वारा एलएलएससी ,इसलिए। था गया बनाया दौरान के अवधि परिचालन इसे और का उत्पादन 1994 ।आदेश पारित को अक्टूबर(पी-10पारि द्वारा एचएलएससी और (त आदेश दिनांक ,अगस्त 5 1998 -पी)12।हैं योग्य जाने किए रद्द (

याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने विद्वान वकील द्वारा यह मामला दर्ज कराया है जिससे , दावा कि हुए करते उम्मीद यह ,है वसूला कर कोई से ग्राहकों अपने ने माननीय कि चलेगा पता याचिकाकर्ता ,है गलतका कहना है कि हर समय यह और होगा मेधावी यह। था संवर्धन जंडू2 नही सवाल कोई ,इसलिए। दूसरी ओर ने याचिकाकर्ता यद्यपि कि दिया तर्क ने शर्मा वकील विद्वान , ,दिसंबर 20 उसने लेकिन ,है किया आवेदन भीतर के अवधि निर्दिष्ट1993 से छूट देने का विकल्प चुना है पॉलिथीन जब ,बैग और शीट के निर्माता अभी भी थे। इसके अनुसार पॉलिथीन बैग और शीट का कोई भी निर्माता 1993 ।होगा नहीं पात्र को दिसंबर 20. उन्होंने आगे बताया कि नियम)ए284 आवेदन से तारीख की करने जारी पत्र प्रमाण या से तारीख की उत्पादन तो या द्वारा (ए)(गय दिया विकल्प का करनेा है। हालाँकि आवेदन से तारीख की उत्पादन ने इकाई की याचिकाकर्ता , जा दी नहीं छूट इसे ,इसलिए। थी गई आ में सूची नकारात्मक वह जब है चुना विकल्प का करने कि है किया प्रस्तुत ने शन्ना श्री। है सवाल का प्रभाव पूर्वव्यापी के नियमों मसौदा तक जहां। सकती केव नियम मसौदाल एक प्रस्ताव था और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। विद्वान वकील के अनुसार मसौदा नियमों को अंततः 1994 ।गया किया अधिसूचित को फरवरी 11(पी-9 प्रभाव भूतलक्षी एवं (सकता जा किया नहीं दावा यह ,इसलिए। गया किया नहीं स्वीकार द्वारा सरकार प्रावधान संबंधित से मसौ कि हैदा नियम के वस्तुओं जैसी शीट और बैग पॉलिथीन बाहर से सूची नकारात्मक जो , ।होगा लागू से तिथि पूर्वव्यापी ,है करता प्रदान लिए के संचालन पूर्वव्यापी

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हमने पाया कि कर के भुगतान से कर छूट पाने के लिए याचिकाकर्ता का अधिकार नियमों के नियम नियम उप के ए 28

3. 4 उपनियम और 3 उपनियम के ए28 नियम के नियमों। होगा निर्भर पर 5 और 4(ए पढ़ना को (

:हैं प्रकार इस जो है अनिवार्य

। है सकती चुन विकल्प का उठाने लाभ का स्थगन या छूट कर इकाई औद्योगिक पात्र एक -विकल्प"

प बार एक्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा सिवाय इसके कि इसे छूट से एक बार बदला जा सकता है*

शेष अवधि के लिए स्थगन और लाभ की संतुलित मात्रा।

पत्र प्रमाण पात्रता या छूट लाभ का स्थगन या छूट कर ,अधीन के प्रावधानों अन्य के नियम इस (ए)

दिय को इकाई औद्योगिक पात्र वाली रखनेा जाएगा के अवधि की वर्ष दर वर्ष ,हो मामला भी जैसा ,

90 के वर्ष 5 में "सी" विभिन्नज़ोन। लिए% में से 100% शामिल हैंबशर्ते कि छूट के मामले में लाभ सकल टर्नओवर पर कर तक विस्तारित होगा और स्थगन के मामले में निर्मित द्वारा इकाई यह ,

त कर पर टर्नओवर योग्य कर के मालक विस्तारित होगा।[

बशर्ते कि विस्तार या विविधीकरण के मामले में केवल मौजूदा इकाई की विस्तारित या विविध क्षमता ही इस नियम के तहत किसी निहित में नियमों इन और होगी हकदार की स्थगन या छूट 24 जाए किया विचार पर क्षमता विविध या विस्तारित एक ,बावजूद के बात विपरीत भीगा। बिक्री कर पंजीकरण के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र इकाई अलग एक को इकाई औद्योगिक प्रत्येक ऐसी ^^

।होगा करना प्राप्त प्रमाणपत्र आईईजीआई

नियम के उपरोक्त उद्धरणों का अवलोकन ईआई एक लाभ का स्थगन या छूट कर औद्योगिक ^^^

है उपलब्ध लिए के पीसीआरजोड

इकाई जिसे छूट या पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से या वर्ष ,से तारीख की करने जारी इरोम में क्षेत्रों विभिन्न वर्ष-दर-स्थगन या छूट कर अनुसार के विकल्प इकाई औद्योगिक पात्र ,है सकता जा चुना विकल्प कि जैसा

।है हकदार का चुनने विकल्प का उठाने लाभ का व्यायाम किया या छूट कि है आया में रिकॉर्ड यह . अप्रैल 1 अवधि परिचालन की स्थगन,मार्च 31 से 1988 ,1997 तक।

फिर उप28 नियम के नियमों। है प्रक्रिया की उठाने लाभ का लाभ गए किए प्रदान द्वारा नियम--ए का 5(ए:है प्रकार इस जो (

"5इ जो इकाई औद्योगिक पात्र प्रत्येक (ए)स नियम के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है उसे , 70 एसटी फॉर्म में प्रतियों तीन को केंद्र उद्योग जिला महाप्रबंधक भीतर के दिनों 90 से तिथि इसकी उत्पादन वाणिज्यिक। होगा करना आवेदन साथ के प्रतियों सत्यापित की दस्तावेजों उल्लिखित में लाग के नियम इस या जाने में ू होने की तिथि। जाएगा किया नहीं विचार पर ,हो में बाद भी जो , संलग्न। जाएगा किया नहीं विचार पर आवेदन भी किसी पर जाने किए नहीं प्रस्तुत भीतर के समय माना नहीं ऐसा को आवेदन वाले विवरण गलत या अधूरे सहित दस्तावेजों आवश्यक वाले जाने किए म संबंध इस आवेदक यदि। जाएगा ं उसे दिए गए अवसर पर इसे पूरा करने में विफल रहता है तो यह किया जाता है।"

उपरोक्त नियम के अनुसार प्रत्येक पात्र औद्योगिक इकाई को महाप्रबंधक को दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ फॉर्म एसटी की दस्तावेजों को महाप्रबंधक है आवश्यक करना आवेदन में 70 सत्यापित प्रतियों के साथ। जिला उद्योग केन्द्र को व्यावसायिक उत्पादन में आने की तारीख से 90 के समय निर्धारित वह यदि जाएगा किया नहीं विचार पर आवेदन भी किसी ऐसे। भीतर के दिनों में करने पूरा इसे भी बाद के जाने दिए अवसर आवेदक यदि। हो गया किया नहीं प्रस्तुत भीतर र विफलहता है तो अपूर्ण या अपूर्ण विवरण के साथ आवेदन को पूरा नहीं किया गया माना जाएगा।

याचिकाकर्ता ने पॉलिथीन बैग और शीट के निर्माण के लिए अनुसरण के नीति औद्योगिक की 1992 25 लेकिन 1992 ।था में सूची नकारात्मक को मार्च 9 उद्योग उक्त। थी की स्थापित इकाई अपनी में मईको उन्हें नकारात्मक सूची में डाल दिया गया। फरवरी 11 अंततः। द्वारा विभाग औद्योगिक 1993

1994 ।गया दिया हटा से सूची नकारात्मक इसे से(पी-9 नियम द्वारा विभाग कराधान एवं उत्पाद (28-ए में संशोधन कर। इससे पहले संशोधन प्रारूप नियमों की सवारी अधिसूचना दिनांकित थी13 अक्टूबर ,1993 25 न क्यों कि था गया किया प्रकाशित हुए करते आमंत्रित आपत्तियां में (आईएम) 1993 ।जाए दिया कर बाहर से सूची नकारात्मक को निर्माण के शीट और बैग पॉलिथीन से मई. 1 lowcvcr, इसे लेकर निर्णय सचेत में 1994 ।था गया दिया हटा से सूची नकारात्मक से फरवरी 11। याचिकाकर्ता ने इसके वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से जो है किया आवेदन भीतर के दिनों 90 के 28 नियम इकाई की याचिकाकर्ता कि है नहीं विवादित भी यह। है हुआ शुरू से 1993 दिसंबर 20 2 खंड(सी को दावे के याचिकाकर्ता .नियम राजभाषा एक -है इकाई नई एक भीतर के अर्थ के ('एलएलएससी ,अक्टूबर 28 ने '1994 .पृ)1 कि है दिया कर अस्वीकार पर आधार इस केवल को (,फरवरी 11 इकाई की याचिकाकर्ता1994 से पहले उत्पादन में चली गई थी और इसलिए वह उपरोक्त के लिए योग्य नहीं है। लाभ। उपरोक्त आदेश को ,अगस्त 5 दिनांक ने आईएलएससी आई' 1998 -पी)12 के (माध्यम से बरकरार रखा है। अधिसूचना दिनांक ,फरवरी 1111994 -पी)9 का (शामिल वस्तुएं विभिन्न जिसमें। है गया किया संशोधन में 111 अनुसूची जिसमें ,है गया दिया संदर्भ थी गई दिखाई में सूची नकारात्मक पहले जो सामग्री प्लास्टिक और हैं में सूची नकारात्मक जो हैं)9 मार्च ,1992 की अधिसूचना के आइटम नंबर - पी) अनुलग्नक ,पर 182। है गया दिया हटा को (,दिसंबर 20 उत्पादन में इकाई की याचिकाकर्ता कि है सच यह1993 को शुरू हुआ था लेकिन , ,फरवरी 11 द्वारा याचिकाकर्ता1994 को एक आवेदन किया गया था शीट और बैग पॉलिथीन जब , उपलब् ही पहले आदिध हो चुके थे।

• सम तारीख की अधिसूचना द्वारा नकारात्मक सूची से हटा दिया गया।

जैसा कि नियमों के नियम 28-ए के पूर्ववर्ती पैरा उप 4 नियम-(ए यह ,है चुका जा देखा ही पहले में (करने जारी या से तारीख की उत्पादन वाणिज्यिक तो या याचिकाकर्ता कि है बताता से रूप स्पष्टकी

तारीख से कर छूट का लाभ का दावा कर सकता है। उसके विकल्प के अनुसार छूट संबंधी पात्रता/ इसका द्वारा याचिकाकर्ता .है नहीं अपरिवर्तनीय विकल्प उपरोक्त। जाएगी की जारी सीसीआरटीआई तार की उत्पादन वाणिज्यिक या से तारीख की होने जारी प्रमाणपत्र छूट/पात्रता हमेशा दावाीख से किया जा सकता है। नियमों के उप4 नियम-(ए28 नियम और (-ए के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं , 28 नियम तुलना की प्रावधान जब खासकर-ए के उपनियम के 3 उपनियम। है जाती की से 3 के उठाने लाभ का स्थगन या छूट कर द्वारा इकाई औद्योगिक पात्र एक कि चलेगा पता से अवलोकन ए लिएक विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। Iramei o। नियम ने अनुवर्ती उप 4 नियम-(ए अनिवार्य में (अंतिम को विकल्प गए किए प्रयोग बार एक कि हुए करते प्रदान यह ,है किया नहीं उपयोग का भाषा माना जाएगा में सु है गया किया उपयोग का 'करेगा' अभिव्यक्ति कि है उचित देना ध्यान यह - नियम 4 नियम-उप जबकि 3(ए के नियम जो है करता उपयोग का 'है सकता हो' अभिव्यक्ति (4 नियम-उप कि है देता संकेत भी यह को निर्माता(ए विकल्प का नियमों गए किए प्रयोग तहत के (अपरिवर्तनीयनहीं है। यह मानना उचित है कि नियमों का नियम 28-ए राज्य में एक विशेष प्रकार के उद्योगों को रियायत देने वाला एक लाभकारी प्रावधान है। 3 नियम-उप के नियमों मंशा विधायी 1 4 और(ए28 नियम ओएल (-ए की शब्दावली से स्पष्ट है। जहां कहीं भी नियम बनाने वालों का इरादा नियम को अनिवार्य बनाने का था और है किया इस्तेमाल का शब्द 'करेगा' उसने वहां , 28 नियम के नियमों अन्यथा-ए के उप) नियम-3 गया किया इस्तेमाल का शब्द 'है सकता हो' में (के नीति औद्योगिक की 1992 लिए के निर्माण के शीट और बैग पॉलिथीन ने याचिकाकर्ता।है इक अपनी में अनुसरणाई स्थापित की थी। उक्त उद्योग 1992 ।था में सूची नकारात्मक को मार्च 9 अंततः। द्वारा विभाग औद्योगिक 1993 ।गया दिया डाल में सूची नकारात्मक उन्हें को मई 25 लेकिन 1994 ।गया दिया हटा से सूची नकारात्मक इसे से फरवरी 11(पी-9 विभाग कराधान एवं उत्पाद (

अधिसूचना सवारी की नियमों प्रारूप संशोधन पहले इससे। कर संशोधन में ए-28 नियम द्वारा थी दिनांकित

,अक्टूबर 131993 न क्यों कि था गया किया प्रकाशित हुए करते आमंत्रित आपत्तियां में (आईएम) ।जाए दिया कर बाहर से सूची नकारात्मक को निर्माण के शीट और बैग पॉलिथीन से मई 25 1993. 1lowcvcr, इसे निर्णय सचेत में 1994 ।था गया दिया हटा से सूची नकारात्मक से फरवरी 11 किया आवेदन भीतर के दिनों 90 से तारीख की उत्पादन वाणिज्यिक इसके ने याचिकाकर्ता। लेकर नियम इकाई की याचिकाकर्ता कि है नहीं विवादित भी यह। है हुआ शुरू से 1993 दिसंबर 20 जो है क 28े खंड 2(सी दावे के याचिकाकर्ता .नियम राजभाषा एक -है इकाई नई एक भीतर के अर्थ के (,अक्टूबर 28 ने 'एलएलएससी' को1994 .पृ)1 है दिया कर अस्वीकार पर आधार इस केवल को (,फरवरी 11 इकाई की याचिकाकर्ता कि1994 से पहले उत्पादन में चली गई थी और इसलिए वह उपरोक्त के लिए योग्य नहीं है। लाभ। उपरोक्त आदेश को ,अगस्त 5 दिनांक ने आईएलएससी आई' 1998 -पी)12 ,फरवरी 11 दिनांक अधिसूचना। है रखा बरकरार से माध्यम के (1994 -पी)9 का (शामिल वस्तुएं विभिन्न जिसमें। है गया किया संशोधन में 111 अनुसूची जिसमें ,है गया दिया संदर्भ नकारात जो हैं्मक सूची में हैं और प्लास्टिक सामग्री जो पहले नकारात्मक सूची में दिखाई गई थी)9 मार्च ,1992 की अधिसूचना के आइटम नंबर - पी) अनुलग्नक ,पर 182। है गया दिया हटा को (,दिसंबर 20 उत्पादन में इकाई की याचिकाकर्ता कि है सच यह1993 को शुरू हुआ था लेकिन , द याचिकाकर्ता्वारा ,फरवरी 1111994 को एक आवेदन किया गया था और बैग पॉलिथीन जब , ।थे चुके हो उपलब्ध ही पहले आदि शीट

याचिकाकर्ताओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित किया गया था और वास्तव में उन्हें उत्पादन शुरू होने की तारीख से बिजली शुल्क से छूट .पी)5(, इसके द्वारा खरीदे गए जेनरेटिंग सेट पर सब्सिडी .पी)6(, आवंटन जैसे विभिन्न लाभ दिए गए थे। इंडस्ट्रियल इस्टेट .पी) कमल ,7 (

लाख 10 लिए के चलाने उद्योग द्वारा एचएफसी .ऋण का .रु लगभग और प्लॉट औद्योगिक में .पी)8 दिसंबर 20 में इकाई की याचिकाकर्ता कि है मानना हमारा ,इसलिए। (को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख होने के आधार पर लाभ से इनकार किया जाए। में सूची नकारात्मक को 1993 तारीख की उत्पादन वाणिज्यिक जब तब खासकर ,होगा नहीं उचित और न्यायसंगत करना शामिल जा किया जारी पत्र प्रमाण छूट या पत्र प्रमाण पात्रता जब से तारीख की बाद उसके या सेता है ऐसे , उस इकाई की याचिकाकर्ता कि है निर्विवाद यह। है गया दिया विकल्प का करने दावा का लाभों के देने पत्र प्रमाण पात्रता लिए के उठाने लाभ का छूट कर बिक्री जब है पात्र से प्रकार सभी को तारीख प्रमा छूट/पात्रता तो या छूट ,तदनुसार। था गया किया दायर आवेदन लिएणपत्र जारी होने की तारीख से या वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दी जा सकती है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख को चुना है यह मतलब इसका ,थी में सूची नकारात्मक वह जब , दिय नहीं से तारीख की करने जारी प्रमाणपत्र छूट/पात्रता इसे कि होगा नहींा जा सकता है क्योंकि नियम अनिवार्य नहीं है। इसलिए जारी प्रमाणपत्र छूट/पात्रता एलएलएससी * कि है विचार हमारा , लिए के करने विचार पर आवेदन के याचिकाकर्ता लिए के देने छूट से कर बिक्री से तारीख की करने रखन में सूची नकारात्मक को उद्योग के याचिकाकर्ता जब ,था बाध्ये पर रोक थी। हटा दिया गया है। तदनुसार यह माना जाता है कि ,अक्टूबर 28 दिनांक आदेश पारित द्वारा 'एलएलएससी'1994 .पृ)10 ,अगस्त 5 द्वारा 'एचएलएससी' और (1995 .पृ)12 में नजर की कानून आदेश पारित (जाने रखे अलग हैं और हैं नहीं टिकाऊयोग्य है।एससी को आवेदन की तिथि पर याचिकाकर्ता यूसीटी के दावे पर विचार करने की स्वतंत्रता होगी। इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से चार की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

के. कन्नन न्यायमूर्ति के समक्ष

पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम, Pe/7

बनाम

पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पंजाब

और अन्य,-उत्तरदाता

2000 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5624

7 अक्तूबर, 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 25-च-प्रबंधन कामगारों को ठेके पर रखना और समय-समय पर अवधि बढ़ाना-अनुचित श्रम व्यवहार-अधिकरण 12 कैलेंडर महीनों की अवधि के दौरान केवल 240 दिनों के पूरा होने पर नियमितीकरण के लिए कामगारों की मांग को खारिज करता है अधिकरण ने नियमितीकरण के लिए प्रत्येक कामगार के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जो योजना या अनुदेशों के अनुसार चार वर्ष की अवधि के लिए लगातार सेवा में रहा था पीईएससीओ द्वारा किया गया या अपनाया गया - कामगारों के पक्ष में औद्योगिक अधिकरण के निष्कर्ष संविदात्मक नियुक्तियों की प्रकृति और अनुचित प्रयोगशाला ^ प्रथा जिसमें प्रबंधन लिप्त था और रखरखाव के संबंध में वस्तु प्रबंधन पूर्णत न्यायोचित था-याचिका लागत के साथ खारिज कर दी गई।

यह माना जाता है कि सभी संगत ब्यौरों और इस विषय पर केस लॉ की जांच में परिवर्तन करते हुए, औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने कामगारों के पक्ष में संविदात्मक कार्यों की प्रकृति और अनुचित श्रम व्यवहार की ओर इशारा करते हुए निर्णय दिया था जिसमें प्रबंधन लिप्त था। यह भी माना गया कि प्रबंधन की आपत्ति कि reference बनाए रखने योग्य नहीं था, स्पष्ट रूप से अस्थिर था। औद्योगिक ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण पूरी तरह से उचित है। इन सभी वर्षों में, उस समय से जब ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है, पीईएससीओ ने केवल अपने नासमझ मुकदमेबाजी के माध्यम से अपने पैरों को खींच लिया है और एक न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास किया है जिसे श्रमिकों द्वारा उनके संघ के माध्यम से गति में स्थापित किया गया था। इस बीच, यह कई आकस्मिक कृत्यों में भी लिप्त रहा है जिसने प्रबंधन और कामगारों के बीच औद्योगिक तनाव को बढ़ा दिया है। यह इस संदर्भ में है कि श्रमिकों की अन्य मांगों या शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए कि वे सभी पीड़ित हो रहे थे।

(पैरा 10)

आगे कहा गया कि रिट याचिका पूरी तरह से परेशान करने वाली है। संदर्भ की विचारणीयता के संबंध में की गई आपत्तियां, जिनका औद्योगिक अधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से उत्तर दिया गया था, का मेरे समक्ष आग्रह नहीं किया गया था। विद्वान वकील ने केवल इस मुद्दे तक खुद को सीमित रखा कि सचिव, *कर्नाटक राज्य* बनाम उमा देवी और अन्य, 1996 (4) एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के बयान को देखते हुए नियमितीकरण निश्चित रूप से अब कोई मामला नहीं हो सकता है। किसी भी निर्णय में इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थितियों के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।

(पैरा 13)

पी.के. मुटनजा, एसएस सूडान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

रवि कांत *शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।*

के. कन्नन, जे.

I. जांच का दायरा:

(1) पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम (जिसे इसके बाद पीईएससीओ कहा गया है) ने उपर्युक्त रिट याचिका में औद्योगिक अधिकरण के पंचाट को चुनौती दी है जिसमें मांग स्वीकार करने वाले कामगारों के पक्ष में एक संदर्भ का उत्तर दिया गया है

नंबर 4 और 10 और अन्य मांगों को इंजेक्ट करना। मांग संख्या 2 के रूप में काम करने वाले इकबाल सिंह को बहाल किया गया था। मांग संख्या 4 और 10 को एक साथ लिया गया था और उसका निपटान किया गया था। चूंकि संदर्भ का उत्तर देनेवाले औद्योगिक अधिकरण की वैधता को अन्य आधारों पर चुनौती दी गई है कि अधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, इसलिए मांग, सरकार द्वारा संदर्भ के विषय और औद्योगिक अधिकरण द्वारा उनसे कैसे निपटा गया है, इसकी जांच करना आवश्यक हो जाता है।

(ii) विवादों का कारण :

(2) रिट याचिका केवल तब तक ही सीमित है जब तक ट्रिब्यूनल ने मांगों संख्या 4 और 10 को स्वीकार किया है, जो निम्नानुसार हैं: -

> "मांग नंबर 4: क्या प्रतिष्ठान के कामगार, जिन्होंने 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, नियमित होने के हकदार हैं? यदि हां। किस विस्तार के साथ?
>
> 'मांग संख्या 10: क्या प्रबंधन को पीईएससीओ की शाखाओं के साथ-साथ आई लीड ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना चाहिए?

मांगें अनिवार्य रूप से इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि श्रमिकों को कई वर्षों तक ठेके पर रखा जाता था, समय-समय पर समय-समय पर बढ़ाया जाता था, हालांकि, श्रमिकों के अनुसार, सगाई की प्रकृति ऐसी थी कि काम हमेशा उपलब्ध था और प्रबंधन जानबूझकर अनुचित श्रम पद्धति अपना रहा था और उन्हें टेंटरहुक पर रखकर और उन्हें वार्षिक वेतन

वृद्धि के साथ वेतन के नियमित वेतनमान से वंचित कर रहा था। सरकार द्वारा किए गए संदर्भ में न्यायनिर्णयन के लिए कामगारों की सभी मांगों को केवल पुन प्रस्तुत किया गया था और प्रबंधन द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर कि संदर्भ स्वयं खराब था और अनुरक्षणीय नहीं था, श्रम न्यायालय ने इस विवाद के संबंध में संदर्भ पर विचार करने के लिए अधिकरण के क्षेत्राधिकार और क्षेत्राधिकार से संबंधित एक मुद्दा तैयार किया था कि कामगारों के दावों को कानून द्वारा वर्जित किया गया था।

(iii). पीईएससीओ की गतिविधियों के संबंध में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जांच:

(3) औद्योगिक अधिकरण ने पीईएससीओ के गठन और उन विभिन्न कार्यकलापों का विस्तार से उल्लेख किया था जो उसने कामगारों से निकाले गए कार्य की जांच करने के लिए किए थे और जो कार्य कार्य की प्रकृति की जांच करने के लिए किए गए थे

प्रबंधन का कामगारों के नियमितीकरण के लिए योजना न होना न्यायोचित था। पीईएससीओ स्वयं पंजाब सरकार द्वारा अधिनियमित स्थिति का एक प्राणी है, जिसमें मामलों और व्यवसाय के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन को पेस्को अधिनियम की धारा 6 के अनुसार निदेशक मंडल में निहित किया गया है। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष शामिल थे। प्रबंध निदेशक और निदेशक। पंजाब सरकार के तीन जुड़े विभागों के सचिव। उद्योग निदेशक *पदेन* होने के नाते और चार अन्य निदेशक सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों में से नामित किए जा रहे हैं। अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि अध्यक्ष को भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक था जबकि प्रबंध निदेशक को राज्य या केंद्र सरकार का वर्ग-1 होना था, लेकिन उनकी नियुक्ति हमेशा केवल राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक पूंजी राज्य सरकार द्वारा पीईएससीओ में निवेश की गई थी।

(4) अधिनियम की धारा 51(1) के अनुसार पीईएससीओ का कार्य राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और आथक उत्थान की व्यवस्था करना था तथा उपधारा 2 में कृषि विकास, विपणन, लघु उद्योगों, परिवहन और अन्य व्यवसाय, व्यापार या गतिविधि, जैसा भी मामला हो, के लिए कार्यक्रमों की आयोजना और निष्पादन का प्रावधान किया गया था। उप-धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि पीईएससीओ को पूर्व-एससीडब्ल्यूआईसीएमसीएन के सार्वजनिक हित, शोधन क्षमता और कल्याण का उचित संबंध होगा। साक्ष्य के माध्यम से यह सामने आया कि पीईएससीओ की कई इकाइयां थीं, जिनमें ऑटो वर्कशॉप और सिलाई केंद्रों को कारखाना अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत किया गया था। इसने वाहनों की बिक्री और स्पेयर पाट्र्स की बिक्री के लिए आयशर कैंटर ऑटोमोबाइल्स की डीलरशिप ली थी। पेस्को में मारुति उद्योग के वाहनों के लिए कई सर्विस स्टेशन और मामूली मरम्मत कार्यों के लिए एक कार्यशाला भी थी। उपर्युक्त इकाइयों और गतिविधियों के अलावा, पंजाब राज्यों के लिए बुलेट प्रूफ वाहनों के निर्माण के लिए पेस्को एकमात्र प्राधिकृत डीलर भी था। आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर। पीईएससीओ के महाप्रबंधक श्री लक्ष्मणदास के साक्ष्य के माध्यम से यह बताया गया था कि विचारण के समय तक। पीईएससीओ लाभ में चल रहा था और वर्ष 1991-92 से 1995-96 के तुलन-पत्रों को अभिलिखित किया गया था। इसके समक्ष रखे गए साक्ष्यों और प्रबंधन द्वारा किए गए अनेक

कार्यकलापों के आलोक में औद्योगिक रिबुनल ने कामगारों के दावे की जांच की थी। कामगारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे कि प्रारंभ में कई अन्य कामगारों को नियुक्त किया गया था

कामगार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि कई अन्य कामगारों को शुरू में नवंबर 1994 से एक वर्ष की अवधि के लिए 1250 रुपये से 3550 रुपये तक के समेकित वेतन पर नियुक्त किया गया था और सभी लोगों ने मांग के समय 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। नोटिस और वे मांग नोटिस के समय सेवा में निरंतर थे और उन्हें समय-समय पर अनुबंध का विस्तार करते हुए भी सेवा में जारी रखा गया था

अधिकरण ने महाप्रबंधक, श्री लछमन दास द्वारा स्वीकार किया कि कामगारों की निरंतर सेवा तीन या चार वर्षों से किसी भी स्तर पर बाधित नहीं हुई है। प्रबंधन ने उन्हें जारी रखते हुए काल्पनिक ब्रेक भी नहीं लिया था। साक्ष्य और प्रबंधन के समक्ष साक्ष्य में निहित स्वीकारोक्ति को प्रस्तुत करते हुए, औद्योगिक अधिकरण ने पाया था कि व्यावसायिक गतिविधि स्थायी और नियमित प्रकृति की थी और संबंधित कामगारों की सेवाओं की स्पष्ट रूप से अपने कार्यों के निष्पादन के लिए नियमित आधार पर आवश्यकता थी और प्रबंधन द्वारा शुरू में एक अवधि के लिए कामगारों को नियोजित करके अपनाई गई प्रथा कि शुरुआत में एक वर्ष के लिए कामगार को नियोजित करके और बिना किसी विराम के उन्हें वर्ष-दर-वर्ष जारी रखना, कम से कम, अनुचित और कामगारों के शोषण के समान है।

निर्णयों का हवाला दिया गया, जांच की गई:

(ए) *सेवा की लंबाई, नियमितीकरण के लिए हमेशा प्रासंगिक नहीं*

(5) औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता प्रबंधन प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर बनाम एस मणि और अन्य (1) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है। इस मामले में कुछ कामगारों के दावे का उल्लेख किया गया था, जो 1980 और 1982 की अवधि के बीच टिक्का मजदूर (ठेके पर लगे हुए) के रूप में लगे थे, लेकिन जब उनमें से कुछ पर जाली स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था, तो उनके खिलाफ शिकायतें जारी की गई थीं। जब प्रबंधन द्वारा कामगारों के पुननयोजन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और एक औद्योगिक विवाद खड़ा किया गया तो उन्हें रोजगार देने से मना कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने पाया था कि कामगारों ने 240 दिनों की सेवा पूरी कर ली थी और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन किए बिना एक समाप्ति कानून में गलत थी। सुनवाई के दौरान नियमित सेवा की दलील पर जोर दिया गया था और इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 240 दिनों की निरंतर सेवा अपने आप में स्थायित्व का दावा करने का साहस नहीं देगी। इसने यह भी

स्पष्ट किया कि धारा 25-एफ डब्ल्यू-_ (2005) 5 एससीसी 100 के प्रावधानों के साथ गैर-अनुपालन के लिएएक निर्देश जारी किया गया है।

कामगारों को उसी स्थिति में बहाल करना जो वे पहले रखते थे और यह कि कामगार 'टिक्कामजदूर' बने रहेंगे। 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से उस सहजता से निपट रहा था जहां प्रबंधन ने दो सूचियों को बनाए रखा था। एक सूची में उन व्यक्तियों की सूची शामिल है जो नियमित रूप से कार्य कर रहे थे और दूसरी सूची में वे व्यक्ति शामिल थे जिन्हें केवल टिक्का मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नहीं देखा गया है कि उस निर्णय की कोई प्रासंगिकता कैसे होनी चाहिए, इस मामले में हम उन कामगारों की स्थिति के बारे में चिंतित नहीं हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और जो बहाली के साथ-साथ सेवा के नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। यह संदर्भ स्वयं एक विषय के लिए था कि सभी कामगारों को संविदा कामगारों के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रबंधन किसी भी नियमित सेवा के लिए प्रदान नहीं करने की जानबूझकर अनुचित श्रम प्रथा अपना रहा था, हालांकि गतिविधियों की प्रकृति और काम की उपलब्धता ऐसी थी कि नियुक्ति स्थायी आधार पर हो सकती थी। यहां के कामगार केवल इसलिए नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है। दूसरी ओर, वे उन कामगारों के उदाहरण दिखा रहे थे जिन्होंने 240 दिन पूरे कर लिए थे और तीन या चार वर्षों से अधिक समय से काम पर चल रहे थे लेकिन एक बार में केवल एक वर्ष के लिए अनुबंध पर रखे गए थे और प्रबंधन द्वारा समय-समय पर उनकी सेवाओं का विस्तार किया गया था।

(b) *कार्य की अस्थायी प्रकृति, चित्रण - तथ्य I का प्रश्न*

(6) विद्वान वकील ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बनाम अनिल कुमार किशरा और अन्य (2) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया है। उक्त निर्णय व्यक्तियों की एक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए नियुक्त किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ था, जिन्हें उम्मीदवारों के नाम, स्कूल का नाम, जन्म तिथि आदि के ब्यौरों के साथ भरा जाना अपेक्षित था, जब प्रमाण-पत्रों का बैकलॉग क्लियर किया जाना था और बैकलॉग को निपटाने के लिए सेवाओं को नियुक्त किया गया था। जब बैकलॉग को निपटा दिया गया था और भविष्य में प्रमाण पत्र तैयार करने का काम कम्प्यूटरीकृत हो गया था, तब कामगारों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई थी। सेवा

से विच्छेदन को चुनौती दी गई थी। सेवा के नियमितीकरण के लिए एक तर्क को खारिज करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 240 दिनों के काम को पूरा करने से कानून के तहत नियमितीकरण का अधिकार नहीं होगा। यह निर्णय फिर से उस मामले में लागू नहीं होता है जहां श्रमिकों का दावा एक अलग आधार पर था जैसा कि समझाया गया है

(2) (2005)5 एससीसी 122

काम की उपलब्धता और नियुक्ति की प्रकृति ऐसी थी कि प्रबंधन उन्हें अनुबंध के माध्यम से केवल थोड़े समय के लिए नहीं रख सकता था। गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड (3) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक और फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस विशिष्ट स्थिति से निपटा है जहां कामगार ने यह विवाद उठाया था कि प्रबंधन आकस्मिक या अस्थायी काम पर रखने की प्रथा में लिप्त था। इस प्रश्न के निर्धारण को लागू करते हुए कि क्या एक अनुचित श्रम का सहारा लिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह तथ्य का प्रश्न आवश्यक था। न्यायालय ने अस्थायी रोजगार का उद्देश्य एकदम स्पष्ट पाया और कर्मचारियों को स्थायी स्थिति के लाभ से वंचित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह निर्धारित किया था कि इस मुद्दे को इस तथ्य के विशुद्ध प्रश्न के रूप में लिया जाएगा कि क्या गतिविधि की प्रकृति को निरंतर कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है या यह विशुद्ध रूप से अस्थायी है। इस मामले में, औद्योगिक अधिकरण ने पीईएससीओ द्वारा चलाई जा रही कई इकाइयों की लाभ अजत करने की प्रवृत्तियों, भूतपूर्व सैनिकों को नियोजित करने के उद्देश्यों, कई गतिविधियों की जांच की है जो प्रबंधन कुछ इकाइयों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों के रूप में पंजीकृत करके कर रहा था, जिनमें से सभी ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि कामगारों द्वारा नियोजित कार्य का तरीका कामगारों को शक्तिहीन बनाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके मनोबल को कमजोर करने के लिए एक छल था उनके कार्यकाल की सुरक्षा और उनके वेतन के पैमाने के संबंध में उनके रोजगार में उचित सौदा। औद्योगिक अधिकरण ने सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद कामगारों की मांग को केवल उन व्यक्तियों के लिए नियमित करने की मांग को खारिज कर दिया था जिन्होंने मांग नोटिस से पहले 12 कैलेंडर महीनों की अवधि के दौरान 240 दिनों की अवधि के लिए लगातार काम किया था। तथापि, इसने प्रत्येक कामगार के मामले को नियमितीकरण के लिए उसके द्वारा बनाई गई या अपनाई गई योजना अथवा अनुदेश, यदि कोई हो, के अनुसार तथा उसके इसकी अनुपस्थिति में हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह (4) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार करने का निदेश दिया

(3) (2007) 1 SCC 533

(4) एआईआर 1992 एससी 2130

(7) यद्यपि सचिव, कर्णाटक राज्य *बनाम* उमा देवी और अन्य (5) में संविधान पीठ के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्णत उचित नहीं है, तथापि इसे इस सीमा तक अधिनीत किया गया कि कोई न्यायालय केवल कुछ दिनों के पूरा होने पर नियमितीकरण का निदेश नहीं दे सकता। यह निर्णय सार्वजनिक रोजगार में नियमितीकरण के निर्देश के संदर्भ में दिया गया है। इस मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने स्वयं कामगारों के नियमितीकरण के दावे को केवल इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया था कि उनमें से कुछ ने 240 दिन पूरे कर लिए थे। इसने प्रबंधन को एक ऐसी योजना तैयार करने के लिए लचीलापन दिया था जो नियमितीकरण के मामले पर विचार करने के लिए न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित था जो अवार्ड की तारीख से पहले चार वर्षों की अवधि के लिए लगातार सेवा में था और यदि कोई योजना या निर्देश नहीं था, इसने निर्देश दिया कि उसे पुरस्कार के प्रकाशन से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करना चाहिए और उन्हें श्रेणी में पेस्को के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य समय वेतनमान के अनुसार वेतन/वेतन का भुगतान करना चाहिए और यदि श्रेणी में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है। पंजाब सरकार के संबंधित या समान श्रेणी के कर्मचारी को स्वीकार्य वेतनमान में (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया कि अधिनिर्णय के प्रकाशन से छह माह की अवधि के भीतर ऐसा किया जाना चाहिए और उन्हें इस श्रेणी में पीईएससीओ के नियमित कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतनमान में मजदूरी/वेतन का भुगतान किया जाए और यदि उस श्रेणी में कोई नियमित कर्मचारी नहीं था, तो फिर पंजाब सरकार के संबंधित या इसी तरह की श्रेणी के कर्मचारी को स्वीकार्य वेतनमान भुगतान किया चाहिए ।

V. निष्कर्ष: संविदात्मक आधार पर नियुक्ति अनुचित श्रम व्यवहार का एक उदाहरण था:

(8) किसी विशेष प्रथा को अनुचित श्रम व्यवहार के रूप में वर्णित करने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम की 5वीं अनुसूची के मद संख्या 10 के माध्यम से उपलब्ध उदाहरणों में लिखा गया है "कामगारों को 'बदलियों' कैजुअल या अस्थायी के <u>रूप में</u> नियोजित करना और उन्हें स्थायी कामगारों के दर्जे और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से वर्षों तक ऐसे ही जारी रखना। प्रासंगिकता का एक और प्रावधान 5वीं अनुसूची का आइटम

(5) 1996 (4) SCC 1

नंबर 5 है जो खंड (ए) और (बी) के माध्यम से निर्धारित करता है कि यदि किसी कामगार को उत्पीड़न के माध्यम से छुट्टी दे दी जाती है या बर्खास्त कर दिया जाता है, या अच्छे विश्वास में नहीं, लेकिन नियोक्ता के

अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, तो नियोक्ता की ओर से यह एक अनुचित श्रम व्यवहार होगा।

अनुचित श्रम व्यवहार से संबंधित प्रावधान 1982 के केंद्रीय अधिनियम 46 द्वारा अधिनियम में डाला गया था जिसे 21 अगस्त, 1984 से लागू किया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल एक विशेष अवधि के लिए एक संविदात्मक नियोक्ता अधिनियम की योजना के लिए एक अभिशाप है। गतिविधियों के आधार पर उदाहरण जो विशुद्ध रूप से अस्थायी हैं जैसे कि जब कुछ परियोजनाएं शुरू की जानी हैं, जो एक समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएंगी अधिनियम धारा 2(ओओ) में शामिल खंड (बीबी) के माध्यम से संविदात्मक रोजगार प्रदान करता है, जिसे 1984 के अधिनियम 49 द्वारा डाला गया था और 18 अगस्त 1984 से लागू किया गया था ताकि प्रबंधन के लिए उचित वर्गीकरण लेना हमेशा स्वीकार्य हो। ऐसे श्रमिक जिन्हें उन क्षेत्रों के संबंध में स्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है जहां गतिविधि नियमित और स्थायी है और ऐसी गतिविधियों के अस्थायी चरित्र के आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए एक अन्य श्रेणी में लगाया जा सकता है।

(9) इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या एक ऐसे संगठन के लिए जो क़ानून का प्राणी है और जिसके स्थायित्व की गारंटी है, जो उन गतिविधियों में संलग्न है जो सार्वजनिक हित की सेवा करने के लिए हैं, साथ ही पूर्व सैनिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार दे सकते हैं उनका कार्य केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए और समय-समय पर सेवा का विस्तार करना। हमारे देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभु कार्य होने के कारण, यह क्षेत्रीय गौरव की बात है कि पंजाब सशस्त्र बलों में काम कर रहे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने वीर जवानों की पेशकश करने में अग्रणी है। पूर्व सैनिकों के एक बारहमासी प्रवाह को नागरिक समाज में शामिल करने की आवश्यकता होगी और उत्पादकता में उनके योगदान का तत्काल परिणाम उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक क़ानून द्वारा बनाए गए संगठन में होगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, PESCO लगातार मुनाफा कमा रहा है और एक या दो इकाइयों को छोड़कर, जिनके बंद होने की सूचना है, PESCO के माध्यम से विस्तारित अन्य सभी इकाइयाँ और सेवाएँ काफी नियमित हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने PESCO की गतिविधियों की पूरी योजना की जांच इस संदर्भ में की कि प्रबंधन अपने श्रमिकों को विभिन्न अवधि के लिए अनुबंध पर नियोजित करके और समय-समय पर उनके अनुबंधों को बढ़ाकर उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे संदर्भ में, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिलीप हनुमान ट्रोश्रीका और अन्य बनाम जिला परिषद और अन्य (6) के फैसले का संदर्भ देना पूरी तरह से उचित था कि धारा 2 (ओओ) के उप खंड (बीबी) को अपवाद की प्रकृति में माना जाना चाहिए। यह पूरी तरह से श्रमिकों के पक्ष में है और इस प्रावधान को इस आलोक में समझा जाना चाहिए कि अधिनियम अनुचित श्रम अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है जिसमें अनुबंध पर अस्थायी श्रमिकों की जानबूझकर नियुक्ति शामिल है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने भी बलबीर सिंह बनाम कुरूक्षेत्र बैंक लिमिटेड 7 मामले में इस माननीय न्यायालय के फैसले को दोहराया जब यह बताया गया कि धारा 2(00) के उप खंड (बीबी) की व्याख्या उस मामले

तक सीमित करने के लिए की जानी चाहिए जहां वहफिर से काम करता है यहl^^

(6) 1990 एलआईसी100

(7) 1990 I एलएलजे (पी एंड एच) = 1990-II-एलएलएन 567 (पी एंड एच)

पूरा किया और एक विशिष्ट अवधि के लिए काम पर रखने के लिए समझौते को वास्तविक के रूप में दिखाया जाएगा। इस उपबंध का उद्देश्य बेईमान नियोक्ताओं के लिए ठेके का नवीकरण न करने की आड़ में कामगारों को बाहर निकालने का एक उपयोगी साधन नहीं है, भले ही काम मौजूद हो, जैसे कि वे फ्लोट्सम और जेट्सम थे जिन्हें गहराई से दूर किया जा सकता था। यदि संविदात्मक रोजगार को जारी रहने वाली नौकरियों के खिलाफ नियमित या स्थायी होने के कर्मचारियों के दावों को विफल करने के लिए एक तंत्र के रूप में फिर से संगठित किया जाता है या कर्तव्यों की प्रकृति ऐसी है कि संविदात्मक समझौते का रंग औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ओओ) से बाहर निकालने के लिए दिया जाता है, तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शैलेंद्र नाथ शुक्ला *बनाम* कुलपति के मामले में आयोजित किया गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय (8) तो इस तरह के समझौते को उचित और प्रामाणिक नहीं माना जा सकता *है/*

(10) सभी संगत ब्यौरों और इस विषय पर केस लॉ की जांच करने के बाद, औद्योगिक अधिकरण ने कामगारों के पक्ष में निर्णय दिया था कि संविदात्मक नियुक्तियों की प्रकृति और अनुचित श्रम पद्धति जिसमें प्रबंधन बनाम शामिल है, का उल्लेख किया गया है। यह भी माना गया कि प्रबंधन की आपत्ति कि संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं था, स्पष्ट रूप से अस्थिर था। मेरे विचार से, औद्योगिक अधिकरण का दृष्टिकोण पूर्णत न्यायोचित है। इन सभी वर्षों में, उस समय से जब ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है, पीईएससीओ ने केवल अपने नासमझ मुकदमेबाजी के माध्यम से अपने पैरों को खींच लिया है और एक न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया को विफल करने का प्रयास किया है जिसे श्रमिकों द्वारा उनके संघ के माध्यम से गति में स्थापित किया गया था। इस बीच, इसने कई आकस्मिक कृत्यों में भी लिप्त रहा है जिससे प्रबंधन और कामगारों के बीच औद्योगिक तनाव बढ़ गया है। यह इस संदर्भ में है कि श्रमिकों की अन्य मांगों या शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए कि वे सभी पीड़ित हो रहे थे।

VI. अत्यचार /उत्पीड़न के उदाहरण:

(11) मांग संख्या 10 सर्वव्यापी फैशन में थी कि प्रबंधन को पीईएससीओ की शाखाओं

के साथ-साथ प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना चाहिए। श्रमिकों द्वारा महसूस किए गए उत्पीड़न की प्रकृति को समझाने की मांग की गई थी कि जो भी श्रमिक संघ की गतिविधियों में शामिल हुए थे या सक्रिय रूप से भाग लिया था, उन्हें व्यवस्थित रूप से संगठन से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने एक मामले की ओर इशारा किया श्री के सदा शिवम, संघ के अध्यक्ष, जिन्हें कामगारों के संघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। एक अन्य व्यक्ति, श्री पी.एस.सोहल, संघ के महासचिव ने इस तथ्य का विवरण दिया कि संघ 4 अक्टूबर, 1995 से पंजीकृत हो गया था और प्रबंधन ने उत्पीड़न के अपने रास्ते तभी बंद कर दिए थे, जब यूनियन पंजीकृत हुई थी। एक अन्य व्यक्ति इकबाल, हेल्पर ने 24 जून 1992 को 89 दिनों के लिए सेवा में शामिल हुए थे और जैसे ही वह संघ में शामिल हुए, उनकी सेवाएं 26 जनवरी 1996 को समाप्त कर दी गईं। यह बिल्कुल अलग बात है कि उक्त कर्मचारी को बाद में बहाल कर दिया गया था। यूनियन के गठन के संबंध में कैप्टन लक्ष्मण दास, जो प्रबंध निदेशक थे, का रवैया सेना में उनकी लंबी भागीदारी की याद दिलाता है, जहां वर्दीधारी लोगों के लिए यूनियन बनाना अस्वीकार्य होता, लेकिन लाभ के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में लगे पूर्व सैनिक इसमें शामिल नहीं थे। एक ही लीग .श्रमिक संघों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने और अपनी शिकायतों को व्यक्त करने में वे पूरी तरह से उचित होंगे। उत्पीड़न की शिकायत करने वाली मांग की जांच औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा केवल इस संदर्भ में की गई थी कि कैसे श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और जिस प्रबंधन को सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया था, उसे एक नए प्रतिमान में समायोजित नहीं किया गया था क्योंकि किसी भी श्रमिक संघ की गतिविधियों के प्रति असहिष्णुता और वे अपने पूर्वाग्रहों में उलझे हुए थे।

(12) औद्योगिक अधिकरण का अधिनिर्णय वास्तव में प्रबंधन के लिए अपने तौर-तरीकों को सुधारने और अपने औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आंखें खोलने वाला रहा होगा। इसके बजाय उन्होंने कामगारों को लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में उलझाकर मनमुटाव बढ़ने दिया है और दिल की जलन बढ़ गई है। औद्योगिक अधिकरण ने केवल यह निदेश दिया था कि यूनियनों में भाग लेने वाले कामगारों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसमें शायद ही कोई संदेह हो सकता है कि यह एक विवादास्पद मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन इसे एक आदर्श औद्योगिक नीति के रूप में अपनाया जाना चाहिए था। दूसरी मांग यह थी कि जिन कामगारों को ठेके पर अल्प अवधि के लिए नियोजित किया गया था, लेकिन वास्तव में उन्हें आवधिक विस्तार द्वारा लंबे समय तक जारी रखा गया था, वे उचित थे कि नियमितीकरण की नीति विकसित करके कामगारों को कार्यकाल की सुरक्षा के लिए विचार करने की आवश्यकता थी।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्देश को अपने स्वयं के तरीकों को बेहतर बनाने और कामगारों को उनके हक की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जागृति के आह्वान के रूप में लिया जाना चाहिए। इसके बजाय, प्रबंधन इस अदालत के समक्ष दलील दे रहा है कि जिन लोगों ने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, वे नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं। यह बिल्कुल भी कामगार की दलील नहीं थी। एक निगम जिसकी उत्पत्ति क़ानून से हुई है और जो उत्पादन गतिविधियाँ चलाता है और अपने कर्मचारियों के काम के माध्यम से मुनाफा कमाता है, उसे उनके साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। जो भूतपूर्व सैनिक निगम से जुड़े हुए हैं, वे भूसे के आदमी नहीं हैं, मिट्टी से नहीं उठाए गए हैं, और यदि वे गंदगी में लोटते हैं तो यह उन पुरुषों और महिलाओं की धरती माता की धूल है, जिन्होंने इसके लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं देश की रक्षा के लिए

(13बुद्धि याचिका पूरी तरह से कष्टप्रद है। संदर्भ की रखरखाव के संबंध में ली गई आपत्तियां जिनका औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से उत्तर दिया गया था, मेरे समक्ष आग्रह नहीं किया गया था। विद्वान वकील ने खुद को केवल इस मुद्दे तक ही सीमित रखा कि ऊपर उल्लिखित उमा देवी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के स्वरूप को देखते हुए नियमितीकरण अब कोई स्वाभाविक मामला नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि इस मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थितियों पर किसी भी निर्णय की कोई

प्रयोज्यता नहीं है।

(14) रिट याचिका रुपये की लागत का आकलन करते हुए खारिज की जाती है। 10.000. औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा नियमितीकरण के लिए तैयार की जाने वाली योजना को अब चार महीने की अवधि के भीतर शुरू और पूरा किया जाएगा

R.N.R.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी